राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 19 मार्च 2025 वर्ष-8,अंक-28 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

नागपुर में कब्र की चादर जलाने की अफवाह पर भड़की हिंसा

-विधानसभा में हंगामा, सीएम बोले- हिंसा एक सुनियोजित साजिश

मुंबई।

नागपुर में भड़की हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को हंगामा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पर कब्र की चादर जला दी। इसके बाद अफवाह फैल गई कि उस पर धार्मिक चिह्न था, जिससे माहौल गर्म हो गया और हिंसा भड़क उठी।

सीएम फडणवीस ने कहा कि करीब 80 से 100 लोगों की भीड़ हिंसा में शामिल थी, जिन्होंने पथराव किया और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, वहीं तीन डीसीपी स्तर के अधिकारियों पर भी हमला हुआ। हिंसा में कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया। सीएम ने कहा कि यह हिंसा एक अफवाह के चलते फैली, जिसमें कहा गया कि जो चादर प्रतीकात्मक कब्र पर रखी थी, उसमें धार्मिक चिन्ह था। इस अफवाह ने विवाद को हवा दे दी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता।

सीएम फडणवीस ने सदन को बताया कि नागपुर हिंसा में अब तक 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक क्रेन और दो जेसीबी समेत चार पहिया वाहन जलाए गए हैं। तलवार से कई लोगों पर हमला किया गया और कुल 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें तीन डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा पांच आम नागरिकों पर भी हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और अब तक पांच मामले दर्ज किए गए हैं। स्थिति को देखते हुए 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है और एसआरपीएफ की पांच टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब कौन है? वह एक कलंक है। नागपुर में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन कल अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। यह कौन-सा आंदोलन करने का तरीका है? शिंदे ने सवाल उठाया कि हमलावरों के पास पेट्रोल बम कहां से आए? उन्होंने कहा कि यह सोची-समझी साजिश थी, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए और कुल 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

शिंदे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आप सीएम की तुलना औरंगजेब से कर रहे हो? औरंगजेब देशद्रोही था, आप उसकी तुलना शिवाजी महाराज से कर रहे हैं? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग और चादर जलाने को लेकर भड़की हिंसा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल मच गया। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता आमने-सामने आ गए।

बहुचर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार में 44 साल बाद 3 दोषियों को फांसी की सजा

24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई

मैनपुरी ।

बहुचर्चित दिहुली सामूहिक नरसंहार मामले में 44 साल बाद आखिरकार फैसला आ ही गया। अदालत ने नरसंहार मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जाति आधारित हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने मामले में दोषियों के खिलाफ प्याप्त सबूत पाते हुए उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट यानि सजा ए मौत दी। इसके साथ ही इन सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दिहुली सामूहिक नरसंहार के मामले में रामसेवक, कसान सिंह और राजपाल को प्याप्त सबूतों के आधार पर दलितों की घरों में घुसकर हत्या करने के मामले में फांसी और तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। 18 नवंबर 1981 को जसराना स्थिति गांव दिहुली में जाति आधारित हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। यहां घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुष और बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि बदमाशों ने लगातार तीन घंटे तक गोलियां बरसाई, जिसमें 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में दिहुली के रहने वाले लायक सिंह ने 19 नवंबर को जसराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई टली

वाराणसी ।

सिखों पर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि राहुल गांधी के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत में वकालतनामा दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 अप्रैल तय की है। तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की है। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सिखों के लिए भारत में अच्छा माहौल नहीं है। ऐसे बयान से देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कर रहे हैं।

1 अप्रैल से इन नंबर पर नहीं चलेगा यूपीआई, चेंक करें कही आपका नंबर तो नहीं

नई दिल्ली ।

आपका बैंक में अकाउंट या फिर आप यूपीआई का यूज करते हैं, तब आपके लिए ये खबर जरूरी है। क्योंकि अगले महीने से बैंक एक महत्वपूर्ण बदलाव करने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से बैंक खातों, गूगलपे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई एप से जुड़े उन यूजर के अकाउंट को बंद कर रहा है जिनका मोबाइल नंबर काफी समय से निक्रिष्य है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बैंकों और इन एप को 31 मार्च तक इसतरह नंबर हटाने का निर्देश दिया है। बदलाव का उद्देश्य निकिष्य या रीसाइकिल किए गए मोबाइल नंबरों से होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। बता दें कि अगर किसी नंबर का इस्तेमाल 90 दिनों तक वॉयस कॉल, एसएमएस या डेटा के लिए नहीं हुआ है, तब वहां नंबर निकिष्य हो जाता है। इसतरह के नंबर फिर से नए यूजर्स को दिए जाते हैं। इसके बाद जब ये नंबर आपके बैंक और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े होते हैं, तब समस्याएं हो सकती हैं। किसी भी पेमेंट के लिए मोबाइल नंबर जरूरी होगा है। यदि आपके नंबर में कोई समस्या है, तब लेन-देन विफल हो सकता है। कई यूजर्स अपने बैंक खातों या यूपीआई एप से कई नंबर लिंक करते हैं। इसके बाद यदि इनमें से कोई भी नंबर महीनों तक निकिष्य रहता है, तब वहां नंबर डिलीट कर दिया जाएगा।

चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया वीडियो...अमृतकाल में बदल रहा है बिहार

पटना । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वीडियो सांग चमके बिहार, गमके बिहार, अमृतकाल में दमके बिहार जारी कर दिया है। 3 मिनट 43 सेकेंड के गाने में राज्य में एनडीए सरकार की उपलब्धियां को बताया गया हैं। साथ ही बिहार में चल रहे विकास कार्यों को दिखाया गया है। इसमें केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार-प्रसार किया गया है। वीडियो में ज्यादातर योजनाओं की बीजेपी खुद क्रेडिट लेती दिख रही है। हालांकि वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को बहुत कम ही दिखाया गया है। सिर्फ 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही दिखाया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा भी हैं। वीडियो को प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अमृतकाल में बदल रहा है बिहार, फिर एक बार डबल इंजन सरकार। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया है।

रायसीना डायलॉग 2025 : जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल

-द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक कश्मीर पर सबसे लंबा अवैध कब्जा

नई दिल्ली।

रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में निष्पक्षता और संप्रभुता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा बना हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देशों के रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर सबसे लंबे समय से एक विदेशी ताकत का अवैध कब्जा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1947 में भारत की आजादी के दो महीने बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा, चीन ने 1950 और 1960 के दशक में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, कि हम संयुक्त राष्ट्र में एक आक्रमण को लेकर गए थे, लेकिन इसे विवाद बना दिया गया। हमलावर और पीड़ित को एक ही स्तर पर रख दिया गया। दोषी पक्ष कौन थे? इसी के साथ उन्होंने पश्चिमी देशों की भूमिका की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इन देशों ने जानबूझकर पाकिस्तान के आक्रमण को कूटनीतिक विवाद में बदल दिया। इसलिए मेरे इस विषय पर कुछ सवाल हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि यह दिखाता है कि कैसे पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़-मरोड़कर पेश किया। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप पर पश्चिमी देशों के नजरिए की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकारें अपने देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं, उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर भी ऐसा किया जाना चाहिए।

अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया

अफगानिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में तालिबान का उत्थान, पतन और फिर से उभरना इसी पाखंड का परिणाम है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि कैसे तालिबान, जिसे कभी चरमपंथी माना जाता था, अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर सूट-टाई पहनकर दिखाई देता है। जयशंकर ने चुटकी लेते हुए कहा, वे तालिबान जिनकी कभी आलोचना होती थी, अब दोहा और ओस्लो प्रक्रियाओं में सम्मानपूर्वक भाग लेते हैं। लेकिन अब भी अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

रूस और यूक्रेन जंग पर मोदी सरकार के रुख के कायल हुए शशि थरूर

तीन साल पुराने अपने बयान पर हो रहा पछतावा

नई दिल्ली ।

रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में शुरु हुई जंग अभी जारी है। जब पूरी दुनिया में रूस-यूक्रेन जंग से खलबली मची हुई थी तभी कांग्रेस नेता शशि थरूर तब भारत सरकार के रुख के सबसे मुखर विरोधियों में से एक थे। तब उन्होंने भारत के स्टैंड को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। अब तीन साल बाद उन्हें अपने स्टैंड को लेकर पछतावा हो रहा है। कांग्रेस नेता थरूर ने रायसीना डायलॉग 2025 में स्वीकार किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर 2022 में जो रुख उन्होंने अपनाया था, वह सही नहीं था। दरअसल, साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस नेता थरूर भारत सरकार के रुख के सबसे मुखर आलोचकों थे। तब उन्होंने संसद में कहा था कि भारत का रूस-यूक्रेन युद्ध पर अचानक चुप होना यूक्रेन और उसके समर्थकों के लिए निराशाजनक होगा। उन्होंने मोदी सरकार पर मौन रहने का आरोप लगाकर कहा था, रूस हमारा दोस्त है और उसकी कुछ वैध सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन भारत का अचानक इस मुद्दे पर चुप हो जाना यूक्रेन और उसके समर्थकों को निराश करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत इस संवेदनशील मामले में मौन हो गया।

रायसीना डायलॉग 2025 में कांग्रेस नेता थरूर से पूछा गया कि क्या रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति को देखकर उन्हें खुशी है कि भारत ने रुख अपनाया, वह सही था? इस पर शशि थरूर ने माना कि तीन साल बाद उन्हें अपनी उस स्थिति पर अफसोस है।

मणिपुर में हालात हो रहे सामान्य, 7,000 नए आवास मंजूर किए गए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया

नई दिल्ली।

मणिपुर में हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहां हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। हिंसा में बेघर हुए लोगों के लिए करीब 7,000 नए आवास मंजूर कर दिए गए हैं। राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक फंड दिया जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था के लिए सेना व असम राइफल्स की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 286 कंपनियों को राज्य पुलिस के साथ मणिपुर में तैनात किया गया है। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नेशनल हाईवे पर सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि करीब 60 हजार लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। वहीं करीब 7000 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष पैकेज के तहत 400 करोड़ रुपए रिलीफ कैंप ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर हो गए लोगों के लिए सात हजार घरों को मंजूरी दी गई है। मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी, मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी और सरकारी आवास योजनाएं उपलब्ध की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित और बेहतर करने के लिए राज्य में लगातार काम हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मणिपुर में रिलीफ के लिए सौ करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि एनडीआरएफ और 68 करोड़ रुपए की राशि एसडीआरएफ के तहत रखी गई है।

रेल मंत्री वैष्णव ने लालू और ममता की खोली पोल, तब हर दिन एक या दो रेल दुर्घटनाएं होती थीं

1 किलोमीटर यात्रा की लागत करीब 1.4 रुपये, ले रहे सिर्फ 73 पैसे

नई दिल्ली ।

रेल दुर्घटनाओं की हालिया घटनाओं के बाद विपक्ष की ओर से किए गए हमलों के बीच राज्यसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए हर दिन एक या दो रेल दुर्घटनाएं होती थीं जबकि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण संख्या घटकर प्रति वर्ष केवल 30 दुर्घटनाओं तक रह गई है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जब राजद सुप्रीमो लालू यादव रेल मंत्री थे (2005-06) तब कुल 698 दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुई थीं। वहीं ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के दौरान 395 दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, पहले औसतन प्रतिदिन एक दुर्घटना होती थी लेकिन अब यह संख्या घटकर प्रति वर्ष सिर्फ 30 हो गई है। यदि हम 43 रेल दुर्घटनाओं को भी शामिल करें तब कुल दुर्घटनाएं 73 होती हैं यानी पहले जो आंकड़ा करीब 700 था वह अब 80 से भी कम हो गया है जोकि 90 प्रतिशत रेल हादसों की की कमी को दिखाता है।

वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान अपनी कार्यकुशलता को साबित किया है और अब यात्री और माल ढुलाई दोनों में वृद्धि देखी जा रही है।

उन्होंने राज्यसभा को संबोधित कर बताया कि एक किलोमीटर यात्रा की लागत करीब 1.4 रुपये है, लेकिन यात्रियों से सिर्फ 73 पैसे लेते हैं। इस साल भारतीय रेलवे ने 1,400 इंजनों का उत्पादन किया है जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। उन्होंने कहा कि जनरल कोचों की संख्या एसी कोचों की तुलना में 2.5 गुना बढ़ाई जा रही है। साथ ही मौजूदा उत्पादन योजना के तहत 17,000 नॉन-एसी कोचों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज से पूछे सवाल, हर सवाल का उत्तर दिया

कृषि मंत्री ने कहा केंद्र भेदभाव नहीं करता

नई दिल्ली।

संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सवाल जवाब का दौर दिखा। प्रियंका गांधी ने वायनाड में प्राकृतिक आपदा के बाद स्थानीय किसानों से जुड़ा सवाल कृषि मंत्री चौहान से पूछे। इसके जवाब में कृषि मंत्री चौहान से साफ कर दिया कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने आंध्र प्रदेश का उदाहरण देकर कहा कि दिक्कत हुई तब मैं खुद वहां गया था। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पूछा कि विदर्भ पैकेज के दौरान केरल के तीन जिलों को भी जोड़ा गया। वायनाड़ में आई प्रलह को देखकर क्या मंत्रालय वायनाड़ को लेकर कोई स्पेशन रिव्यू करने जा रहा है। इसके अलावा केरल के रबड़ किसान की परेशानियों को देखकर केंद्र कोई कदम उठा रही है। मिर्ची के दामों में उथल-पुथल को देखकर मंत्रालय के पास कोई स्पेशल प्लान है क्या?

प्रियंका के सवालों को जबाव देने के लिए कृषि मंत्री चौहान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि किसान किसान हैं, चाहे केरल का हो या कर्नाटक का। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरह की आपदाएं आती हैं, तब केंद्र सरकार हर राज्य एसबीआरएफ के तहत राज्यों को राशि आवंटित करता है। योजना आयोग अनुशंसा करता है, उसके आधार पर ही ऐसा होता है। उसमें 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का होता है और 25 प्रतिशत राशि राज्य की होती है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि आंध्रप्रदेश और तेजंगाना में दिक्कत हुई थी। अत्यंत बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। केंद्रीय टीम वहां गई थी। वहां स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट भी समिट की थी। इसके आधार पर फिर एनडीआरएफ की राशि राज्य सरकारों को दी जाती हें। केरल को भी एनडीआरएफ के तहत 138 करोड़ दिए गए थे। शिवराज ने प्रियका गांधी के आखिरी सवाल पर कहा कि उन्होंने रेट की बात पूछी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों चीनी के दाम कम हो गए थे। मिर्ची भी मसालों में आती है। हमारी सरकार ने तुरंत यह निर्णय लिया कि रेट चीनी के 11 हजार रुपये प्रति वे विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ सम्बंधी लिए जा रहे निर्णयों का भारत पर प्रभाव

यदि अमेरिका अपने देश में हो रहे उत्पादों के आयात पर टैरिफ में लगातार वृद्धि करता है तो यह उत्पाद अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे और इससे अमेरिकी नागरिकों पर मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ेगा। क्या अमेरिकी नागरिक इस व्यवस्था को लम्बे समय तक सहन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर फार्मा क्षेत्र में भारत से जेनेरिक्स दवाईयों का निर्यात भारी मात्रा में होता है। यदि अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो इससे अधिक नुक्सान तो अमेरिकी नागरिकों को ही होने जा रहा है। भारत से आयात की जा रही सस्ती दवाएं अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएंगी। इससे अंततः अमेरिकी नागरिकों के बीच असंतोष फैल सकता है।

(लेखक- प्रहलाद सबनानी)

अमेरिका में दिनांक 20 जनवरी 2025 को नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ली गई शपथ के उपरांत ट्रम्प प्रशासन आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले बहुत तेज गति से ले रहा है। इससे विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं एवं कई देशों को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंततः आगे आने वाले समय में इन फैसलों का प्रभाव इन देशों पर किस प्रकार होगा।

ट्रम्प प्रशासन अमेरिका में विभिन्न उत्पादों के हो रहे आयात पर टैरिफ की दरों को बढ़ा रहा है क्योंकि इन देशों द्वारा अमेरिका से आयात पर ये देश अधिक मात्रा में टैरिफ लगाते हैं। चीन, कनाडा एवं मेक्सिको से अमेरिका में होने वाले विभिन्न उत्पादों के आयात पर तो टैरिफ को बढ़ा भी दिया गया है। इसी प्रकार भारत के मामले में भी ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि भारत, अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता है अतः अमेरिका भी भारत से आयात किए जा रहे कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा। इस संदर्भ में हालांकि केवल भारत का नाम नहीं लिया गया है बल्कि फ्टिट फोर टेटफ्र एवं फ्ररेसिप्रोकलफ्र आधार पर कर लगाने की बात की जा रही है और यह समस्त देशों से अमेरिका में हो रहे आयात पर लागू किया जा सकता है एवं इसके लागू होने की दिनांक भी 2 अप्रेल 2025 तय कर दी गई है। इस प्रकार की नित नई घोषणाओं का असर अमेरिका सहित विभिन्न देशों के पूंजी (शेयर) बाजार पर स्पष्टतः दिखाई दे रहा है एवं शेयर बाजारों में डर का माहौल बन गया है। अमेरिका में उपभोक्ता आधारित उत्पादों का आयात अधिक मात्रा में होता है और अब अमेरिका चाहता है कि इन उत्पादों का उत्पादन अमेरिका में ही प्रारम्भ हो ताकि इन उत्पादों का अमेरिका में आयात कम हो सके। दक्षिण कोरीया, जापान, कनाडा, मेक्सिको आदि जैसे देशों की अर्थव्यवस्था केवल कुछ क्षेत्रों पर ही टिकी हुई है अतः इन देशों पर अमेरिका में बदल रही नीतियों का अधिक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जबकि भारत एक विविध प्रकार की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः भारत को कुछ क्षेत्रों में यदि नुक्सान होगा तो कुछ क्षेत्रों में लाभ भी होने की प्रबल सम्भावना है। संभवतः अमेरिका ने भी अब यह एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि भारत के कृषि क्षेत्र को टैरिफ युद्ध से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि भारत के किसानों पर इसका प्रभाव विपरीत रूप से पड़ता है। और, भारत यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के किसानों को नुक्सान हो। डेरी उत्पाद एवं समुद्रीय उत्पादों में भी आवश्यक खाने पीने की वस्तुएं शामिल हैं। भारत अपने देश में इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इन उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाता है, ताकि अन्य देश सस्ते दामों पर इन उत्पादों को भारत के बाजार में डम्प नहीं कर सकें। साथ ही, भारत में मिडल क्लास की मात्रा में वृद्धि अभी हाल के कुछ वर्षों में प्रारम्भ हुई है अतः यह वर्ग देश में उत्पादित सस्ती वस्तुओं पर अधिक निर्भर है, यदि इन्हें आयातित महंगी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो वह इन्हें सहन नहीं कर सकता है। अतः यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को सस्ते उत्पाद उपलब्ध करवाए। अन्यथा, यह वर्ग एक बार पुनः गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। भारत ने मुद्रा स्फीति को भी कूटनीति के आधार पर नियंत्रण में रखने में सफलता प्राप्त की है। रूस, ईरान, अमेरिका, इजराईल, चीन, अरब समूह आदि देशों के साथ अच्छे सम्बंध रखकर विदेशी व्यापार करने में सफलता प्राप्त की है। जहां से भी जो वस्तु सस्ती मिलती है भारत उस देश से उस वस्तु का आयात करता है। इसी नीति पर चलते हुए, कच्चे तेल के आयात के मामले में भी भारत ने विभिन्न देशों से भारी मात्रा में छूट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और ईंधन के दाम भारत में पिछले लम्बे समय से स्थिर बनाए रखने में सफलता मिली है।

अमेरिका द्वारा चीन, कनाडा एवं मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ के बढ़ाने के पश्चात इन देशों द्वारा भी अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगा दिए जाने के उपरांत अब विभिन्न देशों के बीच व्यापार युद्ध एक सच्चाई बनता जा रहा है। परंतु, क्या इसका असर भारत के विदेशी व्यापार पर भी पड़ने जा रहा है अथवा क्या कुछ ऐसे क्षेत्र भी ढूढे जा सकते हैं जिनमें भारत लाभप्रद स्थिति में आ सकता है। जैसे, अपैरल (सिले हुए कपड़े) एवं नान अपैरल टेक्सटायल का मेक्सिको से अमेरिका को निर्यात प्रतिवर्ष लगभग 450 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहता है और मेक्सिको का अमेरिका को निर्यात के मामले में 8वां स्थान है। अमेरिका द्वारा मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाए जाने के बाद टेक्सटायल से सम्बंधित उत्पाद अमेरिका में महंगे होने लगेंगे अतः इन उत्पादों का आयात अब अन्य देशों से किया जाएगा। मेक्सिको अमेरिका को 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कॉटन अपैरल का निर्यात करता है एवं 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नान कॉटन अपैरल का निर्यात करता है। कॉटन अपैरल के आयात के लिए अब अमेरिकी व्यापारी भारत की ओर देखने लगे हैं एवं इस संदर्भ में भारत के निर्यातकों के पास पूछताछ की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। इन परिस्थितियों के बीच, टेक्स्टायल उद्योग के साथ ही, फार्मा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, इंजीयरिंग क्षेत्र एवं श्रम आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी भारत को लाभ हो सकता है। यदि अमेरिका अपने देश में हो रहे उत्पादों के आयात पर टैरिफ में लगातार वृद्धि करता है तो यह उत्पाद अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे और इससे अमेरिकी नागरिकों पर मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ेगा। क्या अमेरिकी नागरिक इस व्यवस्था को लम्बे समय तक सहन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर फार्मा क्षेत्र में भारत से जेनेरिक्स दवाईयों का निर्यात भारी मात्रा में होता है। यदि अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो इससे अधिक नुक्सान तो अमेरिकी नागरिकों को ही होने जा रहा है। भारत से आयात की जा रही सस्ती दवाएं अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएंगी। इससे अंततः अमेरिकी नागरिकों के बीच असंतोष फैल सकता है। अतः अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन के लिए टैरिफ को लम्बे समय तक बढ़ाते जाने की अपनी सीमाएं हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र एवं सबसे बड़ा विकसित देश है और इस नाते अन्य देशों के प्रति अमेरिका की जवाबदारी भी है। टैरिफ बढ़ाए जाने के सम्बंध में इक तरफा कार्यवाही अमेरिका की अन्य देशों के साथ सौदेबाजी की क्षमता तो बढ़ा सकती है परंतु यह कूटनीति लम्बे समय तक काम नहीं आ सकती है। अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों में भी असंतोष फैलेगा। कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि नीतियों में अस्थिरता बनी रहे। इसका सीधा सीधा असर विश्व के समस्त स्टॉक मार्केट पर विपरीत रूप से पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यदि यह स्टॉक मार्केट के अतिरिक्त अन्य बाजारों एवं नागरिकों के बीच में भी फैला तो मंदी की सम्भावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। अमेरिका के साथ साथ अन्य कई देश भी मंदी की चपेट में आए बिना नहीं रह पाएंगे। अर्थात, इस प्रकार की नीतियों से विश्व के कई देश विपरीत रूप में प्रभावित होंगे।

अमेरिका को भी टैरिफ के संदर्भ में इस बात पर एक बार पुनः विचार करना होगा कि विकसित देशों पर तो टैरिफ लगाया जा सकता है क्योंकि अमेरिका एवं इन विकसित देशों में परिस्थितियां लगभग समान है। परंतु विकासशील देशों जैसे भारत आदि में भिन्न परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक परेशानियों का सामना करते हुए विनिर्माण क्षेत्र में कार्य हो रहा है, अतः विकसित देशों एवं विकासशील देशों को एक ही तराजू में कैसे तौला जा सकता है। विकासशील देशों ने तो अभी हाल ही में विकास की राह पर चलना शुरू किया है और इन देशों को अपने करोड़ों नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इनके लिए विकसित देश बनने में अभी लम्बा समय लगना है। अतः विकसित देशों को इन देशों को विशेष दर्जा देकर इनकी आर्थिक मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिका को विकसित देश बनने में 100 वर्ष से अधिक का समय लग गया है और फिर विकासशील देशों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है। विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का अधिकार है, अतः विकासशील देश तो टैरिफ लगा सकते हैं परंतु विकसित देशों को इस संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

संपादकीय

...ताकि सेफ रहे सेब

दुनिया को नये टैरिफ युद्ध में धकेलने वाले ट्रंप प्रशासन के दबाव की आंच हिमाचल के सेब उत्पादकों तक भी पहुंच रही है। भारत पर सेब आदि उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाने के दबाव ने हिमाचल के सेब उत्पादकों के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। वे केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अमेरिकी सेब पर टैरिफ कम न किया जाए, अन्यथा लाखों उत्पादकों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी। वे तब से फिक्रमंद हैं जब वर्ष 2023 में आयात शुल्क सत्तर फीसदी से घटाकर पचास फीसदी कर दिया गया था। उनको फिक्र है कि यदि फिर टैरिफ में कमी की गई तो भारतीय बाजार अमेरिका के उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते सेब से पट जाएगा। जिससे घरेलू सेब उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आंकड़े इस गंभीर स्थिति को बयां करते हैं कि वर्ष 2018 में जब टैरिफ बढ़ाए गए तो वर्ष 2022-23 तक अमेरिकी सेब का आयात 1.28 लाख मीट्रिक टन से घटकर सिर्फ 4,486 मीट्रिक टन रह गया था। मौद्रिक संदर्भ में देखें तो यह 145 मिलियन डॉलर से घटकर मात्र 5.27 मिलियन डॉलर रह गया था। सेब उत्पादक इस बात को लेकर चिंतित है कि जब वर्ष 2023 में टैरिफ को फिर से वापस पचास फीसदी पर लाया गया तो आयात में करीब 20 गुना वृद्धि हो गई थी। ऐसे में यदि किसी भी तरह की कमी फिर आयात शुल्क में की जाएगी तो भारतीय बाजार वाशिंगटन सेब से पट जाएंगे। फिर भारतीय प्रीमियम सेब से बहुत कम कीमत पर मिलने के कारण गुणवत्ता का विदेशी सेब उपभोक्ताओं की प्राथमिकता बन जाएगा। खासकर संपन्न तबके की पहली पसंद बन जाएगा। इस चिंता ने घरेलू सेब उत्पादकों की नींद उड़ा दी है। उन्हें डर कि पौष्टिकता व रस की गुणवत्ता में भारतीय सामान्य सेब अमेरिकी सेब का मुकाबला नहीं कर पायेगा। लोगो में आम धारणा रहती है कि विदेशी सेब ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल, अमेरिकी सेब पर टैरिफ घटाने की आशंका से सात लाख सेब उत्पादकों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह यह भी कि अमेरिकी व्यापार वार्ता में कृषि टैरिफ घटाना मुख्य मुद्दा है। हालांकि, भारत जो उच्च आयात शुल्क लगाता है वह सोयाबीन पर 45 फीसदी, मक्का पर 50 फीसदी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 150 फीसदी है। अमेरिकी मांग है कि उसके कृषि निर्यात के लिये अवरोध कम किए जाएं। लेकिन निर्विवाद रूप से व्यापार एकतरफा नहीं हो सकता। अगर भारत को रियायतें देनी ही हैं तो उसे अपने उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिये पारस्परिक बाजारों में पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेब उत्पादक पहले ही सस्ते ईरानी आयातों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। ईरानी सेब भारतीय बाजार में पचास-साठ रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से गैर-प्रीमियम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य मिलना बेहद मुश्किल है। स्थानीय सेब उस दर पर आयातित सेबों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य में उत्पादन व परिवहन लागत ज्यादा है। यह बात जगजाहिर है कि हिमालय के पहाड़ी इलाकों के कारण उच्च उत्पादन लागत से किसान जूझ रहे हैं। जिसमें मशीनीकरण असंभव हो जाता है।

बजट के बराबर कर्ज....? : आज की आर्थिक नीति: 'कर्ज लो घी पियो'....!

(लेखक - ओमप्रकाश मेहता)

समूचे देश में इन दिनों ''आर्थिक सीजन'' चल रहा है, केन्द्र के साथ ही सभी राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताग्रस्त है और इस संकट से निजात के रास्ते खोज रही है, हर साल बजट में दिन-दूनी-रात-चैगुनी वृद्धि हो रही है। किंतु इसकी चिंता सरकार में विराजित राजनेताओं को नही बल्कि भारतवासियों को अधिक हो रही है, गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद न राजनेताओं की मौजमस्ती में कमी दृष्टिगोचर हो रही है और न ही शासकीय वर्ग में, चिंताग्रस्त है तो सिर्फ देश-प्रदेश का आर्थिक बोझ सहन करने वाली बैचारी जनता, पर किया क्या जाए? हमारी प्रजातांत्रिक परम्परा ही ऐसी है आज देश-प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस चरम पर पहुंच गई है कि जितना राज्य सरकार का कुल बजट है, तो उसी के बराबर उतना ही कर्ज भी है। अब ऐसी स्थिति में मूल प्रश्न यह है कि सरकार अपने खर्च पर ध्यान दे या जनता की सुविधाओं पर?

....यहां एक बात और मैं स्वयं पिछले पांच दशक से अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, किंतु मुझे आज तह यह समझ में नही आया कि केन्द्र या राज्य सरकार की बजट को घाटे में ही प्रस्तुत करने की यह परम्परा किसने डाली? और सरकारों का बजट हमेशा घाटे का ही होना चाहिए, यह नियम किसने बनाया? क्या बजट की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने की परम्परा खत्म कर दी गई? बजट घाटे का ही होना क्यों जरूरी है? यह मैं आज तक समझ नही पाया? लेकिन परम्परा है, वह चली आ रही है और सब उसका ईमानदारी से पालन भी कर रहे है, और बजट का यह घाटा ही जनता के आर्थिक शोषण का मुख्य आधार होता है, फ़िर चाहे सरकार किसी की भी क्यों न हो?

आज यदि हम देश को छोड़ अपने राज्य की ही आर्थिक स्थिति की चिंता करें, तो आज की स्थिति में हमारी राज्य सरकार को हर दिन एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है, अब राज्य के बजट प्रस्तुति- करण के मात्र छः दिन बाद ही राज्य सरकार छः हजार करोड़ का नया कर्ज लेने जा रही है, इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही अब तक चार बार कर्ज ले चुकी है, एक जनवरी को पांच हजार करोड़, बीस फ़रवरी को चार हजार करोड़, पांच मार्च को छः हजार करोड और बारह मार्च को फ़िर चार हजार करोड़। इस प्रकार पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार कुल मिलाकर बीस हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। यह कर्ज अगले 24 वर्षों में चुकाना होगा और इसकी ब्याज राशि मूल राशि से भी कई गुना ज्यादा होगी।

वैसे यदि कर्ज की दृष्टि से पूरे देश में पांच राज्यों को देखा जाए तो मध्यप्रदेश पांचवें क्रम पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जिस पर साढ़े नौ लाख करोड़ का कर्ज है, दूसरे क्रम पर राजस्थान है, जिस पर सात लाख छब्बीस हजार करोड़ का कर्ज है, तीसरें क्रम पर उत्तरप्रदेश- सात लाख सात हजार करोड़, चैथे क्रम पर पश्चिम बंगाल- सात लाख छः हजार करोड़ और पांचवें क्रम पर अपना मध्यप्रदेश जिस पर चार लाख इक्कीस हजार करोड़ का कर्ज है। कुल मिलाकर यह कर्ज का आंकड़ा सत्तावन हजार करोड तक पहुंच गया है। इस प्रकार प्रदेश का हर नागरिक हजारों के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन इसकी चिंता किसे? हमारे सत्तारूढ़ राजनेता तो अपनी उसी परम्परागत मौज-मस्ती में डूबे हुए है और प्रदेश का प्रशासनिक वर्ग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के कोई अवसर नही चूकता है और चूंकि कर्ज लेने वाले सत्तासीनों की जेब से कर्ज की राशि अदा होनी नही है। इसलिए इस बात की भी किसी को कोई चिंता नही है, चिंतित सिर्फ आम जनता है, जिसके टेक्स में बढ़ौत्तरी कर यह कर्ज चुकाना है। एक ओर बढ़ती मंहगाई का दौर, दूसरी ओर कर्ज चुकाने के लिए टेक्स में बढ़ौत्तरी ऐसी स्थिति में बैचारी आम जनता करें तो क्या? ....पर इसकी चिंता पांच साल में एक बार वोट के लिए भिखारी की मुद्रा में आने वाले राजनेताओं को बिल्कुल भी नही है, उन्हें आम लोगों की परेशानी से क्या मतलब, उनका तो बस एक ही नारा- ''कर्ज लो घी पियो''।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

(चिंतन-मनन)

नित अभ्यास से दर्शन कर सकते हैं ईश्वर का

सभी शास्त्र कहते हैं कि बिना भगवान को प्राप्त किये मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवान की तलाश के लिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद, कोई गुरूद्वारा, तो कोई गिरजाघर। लेकिन इन सभी स्थानों में जड़ स्वरूप भगवान होता है। अर्थात ऐसा भगवान होता है जिसमें कोई चेतना नहीं होती है।

असल में भगवान की चेतना तो अपने भक्तों के साथ रहती है इसलिए मंदिर में हम जिस भगवान को देखते हैं वह मौन होकर एक ही अवस्था में दिखता है। जब हमारी चेतना यानी इन्द्रियां अपने आस-पास ईश्वर को महसूस करने लगती है तब हम जहां भी होते हैं वहीं ईश्वर प्रकट दिखाई देता है। उस समय भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब व्यक्ति के साथ चल रही भगवान की चेतना व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर में मौजूद ईश्वर की प्रतिमा में समा जाती है और मूक बैठी मूर्ति बोलने लगती है। यह उसी प्रकार होता है जैसे मृत शरीर में आत्मा के प्रवेश करने पर शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है।?

मंदिर में विराजमान मूर्ति वास्तव में एक मृत शरीर के समान है। मृत की पूजा करें अथवा न करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति वही कर सकता है जिसमें चेतना हो प्राण हो। इसलिए तीर्थों में भटकने की बजाय जिस देवता की उपासना करनी हो उसे अपनी आत्मा से ध्यान करें उनकी आत्मा अर्थात परमात्मा से संपर्क करें, परमात्मा की पूजा करें तो, जो फल वर्षों मंदिर यात्रा से नहीं मिल सकता, वही फल कुछ पल के ध्यान से मिल सकता है।

विचार मंथन

पाकिस्तानी सेना के ऊपर 48 घंटे में 57 हमले

(लेखक-सनत जैन)

सत्ता के आतंक और नेताओं के भ्रष्टाचार ने सारी दुनिया के देशों में सरकारों के खिलाफ जन विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। दुनिया के अधिकांश देश इस समय आतंकवादी संगठनों तथा जनता की नाराजी को झेल रहे हैं। कई देशों में सत्ता बार-बार बदल रही है राजनीतिक स्थिरता खत्म होती जा रही है हाल ही में पाकिस्तान की बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान की फौज ने 40 घंटा तक ऑपरेशन चलाकर जैसे -तैसे ट्रेन को छुड़ाया, इसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। जिसमें सेना के जवान भी शामिल थे। इस घटना के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हमला कर दिया। 90 जवानों को मार डालने का दावा आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया है। 48 घंटे के अंदर आतंकवादी संगठनों ने 50 से ज्यादा हमले पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी पर किए हैं। जिससे प्रतीत होता है कि पाकिस्तान गृह युद्ध में फंस गया है। शनिवार और रविवार को 57 हमले सेना पर हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने 16 लोगों की मौत और 40 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इसमें ट्रेन हाईजैक के बाद आत्मघाती बम विस्फोट सबसे घातक हमला माना गया है। पाकिस्तान के तीन प्रांतों के 23 जिलों में लगातार हिंसक वारदाते हुई है। बलूचिस्तान से जो चिंगारी शुरू हुई,उसकी लपटे अन्य प्रांतो में भी पहुंचने लगी है। पाकिस्तान की सरकार को इन दिनों तीन मोर्चे पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। बीएलए ओर टीटीपी के साथ अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की सेना को लड़ना पड रहा है। अफगान के रास्ते पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी हो रही है। जिस पर सेना नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की सरकार पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। राजनीतिक अस्थिरता भी पाकिस्तान का संकट बढ़ा रही है। सरकार आतंकवाद को दबाने का जितना प्रयास कर रही है, उससे ज्यादा आतंकवाद फैल रहा है। एक मच्छर भी जीना हराम कर देता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने आम पब्लिक के ऊपर जो कहर पिछले कुछ वर्षों में बरपाया है। उसके कारण अब आतंकी संगठन हिंसक विरोध कर रहे हैं। जिसके कारण पाकिस्तान सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। पाकिस्तान में जिस तेजी के साथ महंगाई, आर्थिक संकटऔर बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके कारण पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन के कगार पर खड़ा हो गया है। सेना और सरकार राजनीतिक तरीके से मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। जिसके कारण अब पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बलूचिस्तान और ख़ैबर पख्तूनख्वाह के कई इलाकों में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा होने के बाद आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में काफी मजबूत हो गए हैं। आतंकवादी ताकत के साथ सत्ता तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता मिलती हुई दिख रही है। कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जयते, पहले पाकिस्तान की सरकार और सेना ने दमन की पराकाष्ठा को पार किया। अब नाराज जनता और आतंकवादी संगठन मिलकर पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखा रहे हैं। श्रीलंका, बंग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में अराजक्ता की स्थिति पैदा हो गई है। पड़ोसी देश होने के कारण इसका असर भारत में पी पड़ना तय है। भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में इसका असर पड़ना तय है। भारत सरकार को सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

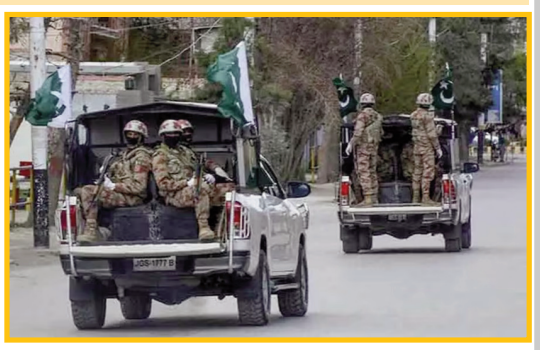

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड के साथ बढ़ाई साझेदारी

नई दिल्ली । वैश्विक स्तर पर उद्यमों के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड के साथ विस्तारित दीर्घकालिक साझेदारी की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी बयान के अनुसार टेक महिंद्रा और गूगल क्लाउड मिलकर उद्यमों को उनके बुनियादी ढांचे और डेटा आर्किटेक्चर को आधुनिक बनाने में मदद करेंगे। साथ ही उनके एआई-संचालित क्लाउड समाधानों से निवेश पर रिटर्न को अनुकूलित करेंगे। टेक महिंद्रा के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) ने कहा कि ये समाधान व्यवसायों को परिचालन संबंधी जटिलताओं से निपटने, दक्षता बढ़ाने और उभरते नियामक मानकों का पालन करते हुए विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम बनाएंगे।

श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन से चीन को सात अरब डॉलर का हुआ नुकसान

कोलंबो । श्रीलंका के बाह्य ऋण पुनर्गठन से चीन को सात अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। मंगलवार को मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई। एक सरकारी समाचार पत्र ने कोलंबो में चीन के राजदूत क्यूई झेनहोंग के हवाले से खबर में कहा कि चीन अक्टूबर 2023 में पुनर्गठन समझौता करने वाला श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय ऋणदाता था। झेनहोंग ने कहा कि हालांकि, जनता को इन विवरणों के बारे में पता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। श्रीलंका ने 2022 के आर्थिक संकट में अपनी पहली चूक की घोषणा करने के बाद 46 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का पुनर्गठन किया था। राजदूत ने साथ ही चीन और भारत के भविष्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के विकास के लिए संयुक्त रूप से काम करने की उम्मीद भी जाहिर की।

मनबा फाइनेंस का बीगौस ऑटो, फिन कूपर्स और प्रॉसपैरिटी से करार

मुंबई । मनबा फाइनेंस लिमिटेड ने बीगौस ऑटो, फिन कूपर्स कैपिटल, और प्रॉसपैरिटी के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। यह साझेदारी कंपनी की ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी और उन्हें अधिक सशक्त बनाएगी। इस साझेदारी के माध्यम से मनबा फाइनेंस लिमिटेड ने उद्देश्य किया है कि भारतीय बाजार में संधारणीय गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाए। ग्राहकों को उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत साझेदारी मिलेगी जो उनकी जरूरतों को समझेगी और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। इस घोषणा से ग्राहकों की आशाएं बढ़ गई हैं और उन्हें विश्वास है कि यह साझेदारी उनके लिए नई और सरल वित्तीय सेवाओं का एक सुनहरा युग प्रदान करेगी। बीगौस ऑटो, फिन कूपर्स कैपिटल और प्रॉसपैरिटी के साथ की इस साझेदारी की उम्मीद की जा रही है और इससे पूरे वित्तीय सेक्टर में एक नया उत्साह भी बढ़ा है।

एरिशा ई मोबिलिटी को यूएई से मिला एक अरब डॉलर का निवेश

नई दिल्ली । भारतीय कंपनी एरिशा ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिष्ठित राणा समूह के इकाई के साथ एक निवेश की घोषणा की है। इस साझेदारी के जरिए कंपनी ने यूएई के एक प्रमुख निवेशक के साथ एक अरब डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के व्यापक विस्तार के साथ-साथ स्थिरता की बढ़ती अवधारणा को साकार करना। एरिशा ई मोबिलिटी की यह महत्वपूर्ण साझेदारी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। इसे स्मार्ट इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता की खरीद, और ऊर्जा समाधानों के तंत्र का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया है। इस साझेदारी के माध्यम से कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाने का मंजिल छूने की दिशा में अग्रसर होगी। इस निवेश से एरिशा ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका क्षेत्र में विस्तार के लिए मजबूत प्रक्रिया किया जा सकेगा।

हैरियर ईवी एसयूवी के इंटीरियर की दिखाई झलक

नई दिल्ली ।

भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी अपकमिंग हैरियर ईवी ऑल-व्हील-ड्राइव के फीचर्स और कंपैटिबिलिटी का खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीज़र में इस ईवी एसयूवी के इंटीरियर की झलक देखने को मिली। पहली बार इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शित किया गया था, और यह साल के अंत तक आधिकारिक रूप से लॉन्च हो सकती है। हैरियर ईवी का केबिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें हरमन का 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो नेविगेशन मैप भी दिखाएगा। इसके अलावा, दो-टोन कलर डैशबोर्ड, टच बटन, टॉगल स्विच, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टेरेन मोड्स के लिए डायल और चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेटेड टाटा बैज देखने को मिलेगा। हैरियर ईवी टाटा की नई जनरेशन 2 एक्टिव.ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। यह कंपनी की पहली ऑल-व्हील-ड्राइव ईवी होगी, जिसमें डुअल-मोटर सेटअप होने की उम्मीद है। इसका टॉर्क आउटपुट 500 एनएम होगा और एक बार चार्ज करने पर यह 500

किमी की ड्राइविंग रेंज दे सकती है।

यह ह्युंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ई-विटारा और महिंद्रा बीई 6 जैसे टॉप मॉडल्स को टक्कर देगी। इसके ऊपरी वेरिएंट्स एक्सईवी 9ई से भी इसकी सीधी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। टाटा मोटर्स हैरियर ईवी की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू करने की योजना बना रही है। आईसीई वर्जन की तरह, इस ईवी में पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल म्यूजिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, टाटा ने इस बार व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग फीचर भी शामिल किए हैं।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को रुपया 26 पैसे बढ़कर 86.55 रुपये पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में रुपया 10 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.71 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय मुद्रा में तेजी सीमित रही क्योंकि निवेशक बढ़ती वैश्विक व्यापार चिंताओं के संभावित आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे हैं। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 86.71 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दिखाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.81 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 103.56 पर रहा।

भारत के वाणिज्य व्यवस्था में व्यापार घाटा सालाना 14.05 अरब डॉलर रहा

नई दिल्ली । भारत में व्यापार एवं वाणिज्य संक्षेपक आंकड़े जारी होने के बाद दिखा कि फरवरी 2025 में वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में सुधार है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत कम रहा। नए आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात फरवरी महीने में 36.91 अरब डॉलर था, जबकि आयात 50.96 अरब डॉलर रहा। इसके बावजूद, आयात में तेज गिरावट के कारण व्यापार घाटा 14.05 अरब डॉलर में पहुंच गया है, जो कि अगस्त 2021 के बाद का न्यूनतम स्तर है। विभागीय मंत्रालय द्वारा व्यापार के गतिशीलता में देखा जा रहा है कि वैश्विक मांग में कमी और वैश्विक प्रशुल्क युद्ध के प्रभाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों के कारण व्यापार में यह कमी हुई है। इसे एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा जा सकता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा कि निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सावधानी और कठोर प्रयास की आवश्यकता है। देश के कुल निर्यात में सालाना 6.24 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जो कि कुल आयात के साथ संतुलित होने का एक मार्ग दिखा सकता है।

शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1133 अंक , निफ्टी 325 अंक ऊपर आया

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी होने से आया है। यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र है जब बाजार तेजी लेकर बंद हुआ है। आज कारोबार के दौरान ऑटो, मेटल और रियल्टी क्षेत्र में जमकर तेजी आई।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 1131.31 अंक करीब 1.53 फीसदी उछलकर 75,301.26 पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी अंत में 325.55 अंक तकरीबन 1.45 फीसदी ऊपर आकर 22,834.30 पर बंद हुआ।

आज कारोबार के दौरान बीएसई की कंपनियों में जोमैटो का शेयर सबसे अधिक 7 फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, एलएंडटी, महिंद्रा एन्ड महिंद्रा, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और अदाणी पोर्ट्स भी बढ़त में हैं।

जानकारों के अनुसार बाजार में तेजी कारण बड़ी पूंजी वाले शेयरों में अच्छी खरीदारी रही है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही से कंपनियों के आय में सुधार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिससे भी बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

महंगाई के भारतीय रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के लक्ष्य स्तर से नीचे आने की उम्मीदें बढ़ गई है।

बाजार में लगातार दो ट्रेडिंग सेशन में आई तेजी से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 400 लाख करोड़ रुपये के करीब पार पहुंच गया। बाजार में पिछले कुछ समय से आई गिरावट

की वजह से यह 400 लाख करोड़ रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया था।

वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिका में खुदरा बिक्री के अच्छे आंकड़ों के बीच वैश्विक बाजार आज तेजी से कारोबार कर रहे हैं। एशिया में जापान का निक्केई 1.4 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स200 0.44 फीसदी और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.51 फीसदी बढ़ा। वही, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट पर एसएंडपी 500 में 0.64 फीसदी, नैस्डैक कंपोजिट में 0.31 फीसदी की वृद्धि हुई, तथा डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.85 फीसदी की तेजी आई। वहीं गत दिवस भी बाजार ऊपर आया था।

इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स 73,830 अंक के स्तर पर लगभग सपाट खुला। हालांकि खुलते ही यह 280 अंक चढ़कर 74 हजार के पार चला गया था। दूसरी ओर निफ्टी भी 80 अंक बढ़कर 22,480 के स्तर पर पहुंच गया जो 112 अंक की तेजी के साथ 22,509 पर कारोबार कर रहा था।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 10 फीसदी तक उछले

- 50 के पार पंहुचा भाव

नई दिल्ली ।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में मंगलवार को बड़ा उछाल देखने को मिला। ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी के शेयर मंगलवार को इंट्राडे ट्रेड में 10 फीसदी तक उछल गए। इससे पहले सोमवार को कंपनी के शेयर बड़ी गिरावट लेते हुए 50 रुपये से नीचे आ गए थे। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 46.58 रुपए प्रति शेयर पर खुला। शेयर ने इंट्राडे में 51.64 रुपए प्रति शेयर का हाई स्तर और 46.32 रुपए प्रति शेयर का न्यूनतम स्तर छुआ। सुबह शुरुआते में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 9.04 फीसदी की बढ़त लेकर 51.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक की वाहन रजिस्ट्रेशन एजेंसी रोस्मेर्टा डिजिटल सर्विसेज ने शनिवार को कहा था कि वह ओला की सब्सिडियरी

ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने जा रही है। इसके बाद कंपनी के शेयर बुरी तरह लुढ़क गए थे।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच के पास दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेमेंट में चूक हुई है। इस आधार पर याचिका में ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

ट्रंप ने मिशेल बोमन को फेडरल रिजर्व का शीर्ष नियामक नामित किया

वाशिंगटन ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के वित्तीय नियामक कार्यों की देखरेख के लिए मिशेल बोमन को नामित किया है। इस कदम से बड़े बैंकों के लिए नियम ढीले होने की संभावना बढ़ी है। बोमन को 2018 में ट्रंप ने फेड के गवर्निंग बोर्ड में सेवा देने के लिए नियुक्त किया था। वह माइकल बार की जगह फेड के पर्यवेक्षण विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। पिछले महीने बार ने कानूनी लड़ाई से बचने के लिए पद छोड़ दिया था। ट्रंप की ओर से नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी। हालांकि, बार सात सदस्यीय फेड बोर्ड में बने रहे, जिससे ट्रंप को मौजूदा गवर्नर में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोमन नामांकन का बैंकिंग उद्योग के लॉबिंग समूहों ने स्वागत किया है। जिनमें अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन और इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बैंकर्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। उपाध्यक्ष के रूप में, बोमन सबसे शक्तिशाली संघीय बैंक नियामक होंगे और बैंक नियमों में सुधार के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और करेंसी नियंत्रक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इस पद के लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता है, हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें आसानी से मंजूरी मिल जाएगी।

देशभर के कई राज्यों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के भाव

- ब्रेंट क्रूड का भाव टूटकर 70.99 डॉलर प्रति बैरल

नई दिल्ली ।

सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। वैश्विक बाजार में क्रूड का भाव गिरकर 71 डॉलर से नीचे आने का असर मंगलवार को घरेलू खुदरा बाजार में भी दिख रहा है और कई शहरों में आज तेल के दाम नीचे आए हैं. हालांकि, दिल्ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में भी मंगलवार को तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 11 पैसे सस्ता होकर 94.62 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल भी 14 पैसे गिरा और 87.72 रुपये लीटर पहुंच गया है। गाजियाबाद में पेट्रोल 18 पैसे गिरकर 94.44 रुपये और डीजल 19 पैसे गिरकर 87.55 रुपये लीटर हो गया है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 17 पैसे गिरकर 94.94 रुपये लीटर हो गया तो डीजल 16 पैसे सस्ता होकर 87.76 रुपये लीटर बिक रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में भी गिरावट दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव टूटकर 70.99 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। डब्लूटीआई का भाव भी

गिरावट के साथ 67.48 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

वहीं दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 100.76 रुपये और डीजल 92.35 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

बजाज फिनसर्व खरीदेगा आलियांज की बीमा कंपनियों में 26 फीसदी हिस्सेदारी

- दोनों इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सेदारी 74 से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगी

नई दिल्ली ।

बजाज फिनसर्व ने कहा कि उसने आलियांज एसई के साथ शेयर खरीद पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह दो इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर्स–बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा 24,180 करोड़ रुपये में होगा। इस अधिग्रहण के बाद, बजाज ग्रुप की इन दोनों इंश्योरेंस कंपनियों में हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगी। बजाज ग्रुप, बीऐ लिक में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी 10,400 करोड़ रुपये में और बीऐ जिक में 13,780 करोड़ रुपये में खरीदेगा। हालांकि यह अधिग्रहण नियामकीय मंजूरियों के अधीन है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी शामिल है। की शर्तों के तहत, बजाज फिनसर्व लगभग 1.01 प्रतिशत, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लगभग 19.95 प्रतिशत, और जमनालाल संस लगभग 5.04 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे, जिससे प्रत्येक इंश्योरेंस कंपनी में कुल 26 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरी होगी। अधिग्रहण के बाद, बजाज फिनसर्व की हिस्सेदारी दोनों कंपनियों में 75.01 प्रतिशत हो जाएगी।

भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लिए उठा रही बड़े कदम

नई दिल्ली ।

भारत में अमेरिकी कंपनी टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को लेकर बड़े कदम उठा रही है। अब कंपनी ने अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों के सर्टिफिकेशन और होमोलॉगेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, टेस्ला इंडिया मोटर और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने मॉडल वाय और मॉडल 3 कारों के होमोलॉगेशन के लिए दो नए आवेदन जमा किए हैं। होमोलॉगेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वाहन भारतीय सड़कों पर चलने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है। इसमें वाहनों के उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों की जांच की जाती है। इससे पहले, टेस्ला भारत में होमोलॉगेशन के लिए सात आवेदन जमा कर चुकी थी, जिनमें से एक हाल ही में मंजूर हुआ था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चीन में सख्त होते नियमों के कारण मस्क दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार भारत में एंट्री करना चाहते हैं। हालांकि, भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला स्थानीय स्तर पर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करे, जबकि मस्क शुरुआत में आयातित कारों की बिक्री पर जोर दे रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी देखी गई है। 2024 में यह 20 प्रतिशत बढ़कर 99,165 इकाई पहुंच गई, जबकि 2023 में यह 82,688 थी। टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स इस सेगमेंट में अग्रणी हैं।

पिरामल फाइनेंस ने पंजाब एवं सिंध बैंक के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली ।

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कहा कि उसने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-आय वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के धरातल पर पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ रणनीतिक सह-ऋण साझेदारी की है। यह साझेदारी ग्राहकों के पहुंच को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन में मदद करने का एक कदम है। पिरामल फाइनेंस के एक प्रमुख अधिकारी ने इस साझेदारी के बारे में बोलते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें गहरे बाजारों में ऋण पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारा लक्ष्य है ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना और उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना। यह साझेदारी टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और उदार ऋण समाधान प्रदान करेगी, जो कि अर्थव्यवस्था की और से मदद करेगी। इस साझेदारी से प्रभाव, अंडरराइटिंग मानकों में सुधार और उत्कृष्ट ऋण मूल्यांकन उपकरणों के विकास में सहायता मिलेगी। यह साझेदारी भारत के वित्तीय स्थिति को सुधारने और उधारकर्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पी.एस.बी.
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank

Piramal
Finance

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विदेश दौरे पर परिवार के साथ ही रहना चाहेंगे सभी क्रिकेटर : विराट

बेंगलुरू (एजेंसी)। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि विदेश दौरे के लिए परिवार को साथ रखने की अनुमति मिलनी चाहिये। विराट ने कहा कि वह अपने होटल के कमरे में अकेले बैठने की जगह मैदान पर तनावपूर्ण दिनों से निपटने के लिए परिवार का साथ चाहेंगे। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद विदेशी दौरे मे परिवार को साथ रखने पर रोक लगा दी थी। साथ ही कहा था कि केवल 45 दिन से अधिक के दौरे पर खिलाड़ी परिवार के साथ रह सकते हैं। वह भी 14 दिन तक ही।

नये नियम में खिलाड़ियों की पत्नी, बच्चे या महिला मित्र छोटे दौरों पर अधिकतम एक हफ्ते तक उनके साथ रह सकते हैं। हाल में खत्म हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी के परिवार दुबई में थे पर वे टीम होटल में नहीं रुके और परिवारों के ठहरने का खर्च खिलाड़ियों ने स्वयं उठाया। कोहली ने कहा, 'लोगों को परिवार की भूमिका समझाना बहुत मुश्किल है। साथ ही कहा कि हर बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते तो अपने परिवार के पास वापस आना अहम होता है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसका महत्व पता है। कोहली ने कहा कि परिवार के साथ होने से खिलाड़ी को मैदान पर मिली निराशा से जल्दी से उबरने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा, 'मैं अपने कमरे में जाकर अकेले बैठकर उदास नहीं रहना चाहता। मैं सामान्य होना चाहता हूं। तभी आप अपने खेल को एक जिम्मेदारी के रूप में ले सकते हैं। आप बाहर की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करते हैं और फिर आप अपने घर वापस आते हैं, आप परिवार के साथ होते हैं और आपके घर में माहौल बिलकुल सामान्य होता होती है और सामान्य पारिवारिक जीवन चलता रहता है।

उन्होंने कहा, 'इसलिए मेरे लिए यह बहुत खुशी का दिन होता है। जब भी संभव होता है, मैं अपने परिवार के साथ बाहर जाने और समय बिताने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। कोहली ने इस बात से निराश थे क्योंकि ऐसे मुद्दों से जिसका कोई संबंध भी नहीं था, वो लोग भी इन चर्चाओं में शामिल रहे हैं। इस के खिलाड़ी ने कह, 'मुझे इससे बहुत निराशा हुई क्योंकि जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी चर्चा में शामिल किया गया जिन्होंने कहा, 'ओह, शायद खिलाड़ियों को परिवार से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'और अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछें कि क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार हर समय आपके आस-पास रहे? तो वे 'हां ही कहेंगे।

कपिल देव ने विदेश दौरे पर परिवार ना ले जाने वाले बीसीसीआई के फैसले पर रखी राय

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव विदेश दौरे पर क्रिकेटरों के अपने परिवार साथ में रखने के पक्ष में है लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में संतुलित रवैया अपनाया जाना चाहिए। भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला में 1-3 से हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने निर्देश जारी किया कि 45 से अधिक दिन के दौरे में क्रिकेटर अधिकतम 14 दिन तक ही अपना परिवार साथ में रख सकते हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार इससे कम अवधि के दौरे पर खिलाड़ी अधिकतम एक सप्ताह तक ही अपना परिवार साथ में रख सकते हैं। विश्व कप 1983 के विजेता कप्तान ने 'कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनविटेशनल' कार्यक्रम के मौके पर कहा, 'ठीक है, मुझे नहीं पता, यह व्यक्तिगत है। मुझे लगता है कि यह क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। मेरे विचार में आपको परिवार की जरूरत है लेकिन आपको हर समय टीम के साथ रहने की भी जरूरत है।'

हाल में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के परिवार भी दुबई में थे लेकिन वे टीम होटल में नहीं ठहरे थे। परिवार का खर्चा बीसीसीआई ने नहीं बल्कि स्वयं खिलाड़ियों ने उठाया था।

कपिल ने कहा, 'हमारे जमाने में क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि हम खुद ही तय करते थे कि दौरे का पहला चरण क्रिकेट को समर्पित होना चाहिए जबकि दूसरे चरण में परिवार के साथ रहने का आनंद लेना चाहिए। इसमें संतुलन होना चाहिए।' इससे पहले रविवार को कोहली ने विदेश दौरे में परिवार को साथ रखने का समर्थन किया था।

पाक गेंदबाज अली को कीवी बल्लेबाजों ने जमकर पीटा, करियर खतरे में पड़ा

डुनेडिन (एजेंसी)। न्यूजीलैंड दौरे पर गयी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस दौरे से अपना करियर शुरु करने वाले 33 साल के मोहम्मद अली की गेंदों की इतनी पिटाई हुई है कि उनका करियर शुरु होने से पहले ही समाप्त होता नजर आ रहा है। पहले मैच में अली ने तीन ओवरों में ही 25 लुटा दिये थे। वहीं दूसरे मैच भी भी इस पाक गेंदबाज की जमकर पिटाई हुई। दूसरे मुकाबले में उनकी पहली और तीसरे गें पर मेजबान टीम के बल्लेबाज फिन ऐलन ने छक्के लगा दिये। इसके बाद की तीन गेंदों पर भी एक छक्का लगा। इस प्रकार ओवर में कुल 18 रन बने।

वहीं जबकि अगले ओवर में भी अली की गेंदों पर टिम सिफर्ट ने जमकर शॉट लगाये। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का, वहीं दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया। चौथी गेंद पर उन्हें सिफर्ट का मिला पर तब तक इस ओवर में अली ने 16 रन लुट दिये थे जिससे मैच पाक के हाथ से फिसल गया था।

इस मैच में पाक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बारिश से प्रभावित मुकाबले में 15 ओवरों में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 46 और शादाब खान ने 26 रन बनाये। इसे बाद कीवी टीम ने 13 ओवर ओर एक गेंद में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस प्रकार पाक को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।

वरुण का क्रिकेट करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित करने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपने करियर में कई बदलावों से गुजरे हैं। वरुण शुरु से क्रिकेटर बनना चाहते थे पर उनका लक्ष्य स्पिनर नहीं बल्कि तेज गेंदबाज बनना था पर उन्हें अवसर नहीं मिल पाया। ऐसे में टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर प्रवेश का उन्होंने प्रयास किया और कई 40 ट्रायल दिए पर असफल रहे। ऐसे में निराश होकर उन्होंनें क्रिकेट को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना शुरु कर दिया और अंत में आर्किटेक्चर बनने में सफल रहे। इसके बाद इस क्षेत्र में नौकरी शुरु कर दी।

आर्किटेक्ट की नौकरी के दौरान वह शौकिया तौर पर कंपनी की ओर खेलने लगी। इसके बाद काम में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने एक बार फिर क्रिकेटर बनने की ठानी। उनका ध्यान तेज गेंदबाज बनने पर था जिसके लिए उन्होंन कए बार फिर प्रयास किया पर अभ्यास के दौरान घायल हो गये। इसके बाद सभी विकल्प आजमाने के बाद उनका ध्यान स्पिन गेंदबाजी की ओर गया। वह यूट्यूब से ही अनिल कुंबले और एडम जैम्पा की गेंदबाजी देख अभ्यास करने लगे।

उनकी मेहनत रंग लायी। साल 2017 में वरुण ने तमिलनाडु के जुबली क्रिकेट वनडे टूर्नामेंट में 7 मैच में 31 विकेट लिए जिसकी बदौलत उन्हें तमिलनाडु प्रीमियर लीग में मौका मिला। 28 की उम्र में वरुण को आईपीएल में अवसर मिला। उन्हें 2019 में पंजाब ने 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर वे कोलकाता नाइट राइडर से जुड़े और उन्हें अपनी गेंदबाजी से मिस्ट्री स्पिनर कहा जाने लगा। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका मिला। श्रीलंका के खिलाफ 25 जुलाई 2021 को आर.प्रेमदासा स्टेडियम में उन्होंने टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया। वहीं साल 2021 में यूएई में हुए टी-20 विश्वकप में वरुण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इससे वह निराश हो गये पर उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और अभ्यास करते रहे। उनकी मेहनत सफल रही। गत वर्ष आईपीएल में 21 विकेट लेकर इस गेंदबाज ने कोलकाता की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस सीजन के लिए कोलकाता ने उन्हें 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। चैम्पियंस ट्रॉफी में तीन मैच में 9 विकेट लेकर वे टूर्नामेंट के दूसरे सफल गेंदबाज और भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। इस साल भारत-इंग्लैंड के बीच हुई टी-20 सीरीज के 5 मैचों में भी वह 14 विकेट लेकर वे मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे।

भारतीय मुक्केबाजों के लिए खुशखबरी, ओलंपिक में फिर से शामिल होगा बॉक्सिंग

नई दिल्ली। साल 2028 लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों से मुक्केबाजों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, 2028 लॉस एंजिलिस खेलों में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने मंगलवार से शुरू हो रहे 144वें सत्र से पहले इसे मंजूरी दे दी। आईओसी ने पिछले महीने वर्ल्ड मुक्केबाजी को अस्थायी मान्यता दे दी थी जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को दरकिनार करके नयी नियामक ईकाई को अधिकार सौंपे। वहीं आईओसी के 18 से 21 मार्च तक चलने वाले सत्र में थॉमस बाक की जगह नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। इसके साथ ही लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में मुक्केबाजी को शामिल करने के कार्यकारी बोर्ड के फैसले को मंजूरी भी मिलेगी। बाक ने कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि, फरवरी में वर्ल्ड मुक्केबाजी को अस्थायी मान्यता मिलने के बाद हम ये फैसला लेने की स्थिति में थे। सत्र में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा और मुझे यकीन है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद दुनिया भर के मुक्केबाज लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेल सकेंगे अगर उनके राष्ट्रीय महासंघ को वर्ल्ड मुक्केबाजी से मान्यात मिली हुई है। वहीं आईओसी के देखरेख में टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 की मुक्केबाजी इवेंट में हुई थी। लंबे समय से चले आ रहे संचालन संबंधी मसलों और मुकाबलों की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद 2023 में आईबीए की मान्यता रद्द कर दी गई थी।

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की उपकप्तानी करते नजर आयेंगे डू प्लेसिस

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के उपकप्तान के तौर पर उतरेंगे। कैपिटल्स ने एक वीडियो पोस्ट करके उन्हें उपकप्तान बनाये जाने की जानकारी सार्वजनिक की है। फाफ इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि वक कैपिटल्स में आकर बेहद खुश हैं। इससे पहले फाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में थे। इस क्रिकेटर ने अब तक 404 टी20 मैच खेले हैं और 40 साल की उम्र में भी दुनिया भर की लीग में अपने प्रदर्शन के कारण टिके हुए हैं। उन्होंने 383 पारियों में छह शतकों और 78 अर्द्धशतकों की मदद से 32.66 की औसत से 11,236 रन बनाए हैं। फाफ के पास आईपीएल का काफी अनुभव है जिसमें दुबई के साथ तीन सत्र की की कप्तानी का अनुभव भी शामिल है, जिसमें टीम दो सीजन में प्लेऑफ तक पहुंची। इससे कैपिल्सक को लाभ होगा। फाफ ने 145 आईपीएल मैचों में 35.99 की औसत और 136 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 4,571 रन बनाए हैं जिसमें 37 अर्द्धशतक और 96 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। उन्हें पिछले सत्र की नीलामी के दौरान डीसी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस सत्र में अक्षर पटेल टीम के कप्तान बनाये गये हैं। डीसी अपना अभियान 24 मार्च को विजाग में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

शार्दुल को अवसर दे सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स

मुम्बई। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को इस बार आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में किसी ने भी नहीं खरीदा था। शार्दुल अभी जून में शुरू होने रहे इंग्लैंड के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। हाल में घरेलू क्रिकेट में शार्दुल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में इसके आधार पर उन्हें एक टीम आईपीएल में अब भी अवसर दे सकती है। वह टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। उसके कई खिलाड़ी अभी चोटिल हैं। ऐसे में इस तेज गेंदबाजी ऑलराउंड र को जगह मिलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस क्रिकेटर को चेन्नई सपुर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से खेलने आ अनुभव है जिसका लाभ लखनऊ उठाना चाहेगी। माना जा रहा है कि इसी कारण शार्दुल रविवार को अभ्यास के दौरान सुपर जायंट्स की किट पहने दिखे हालांकि अभी तक फ्रेंचाइजी ने अधिकारिक तौर पर उन्हें शामिल करने की कोई घोषणा नहीं की है।

भारतीय धाविका अर्चना जाधव डोप परीक्षण में फेल, चार साल का प्रतिबंध लगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर जनवरी में डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण मंगलवार को चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्चना ने बार-बार याद दिलाने पर भी डोप परीक्षण में असफल रहने के खिलाफ अपील नहीं की जिससे विश्व एथलेटिक्स ने यह मान लिया कि वह अपना अपराध स्वीकार करती है और इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया।

विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट (एआईयू) के अनुसार जाधव का जो नमूना पिछले साल दिसंबर में पुणे हाफ-मैराथन के दौरान लिया गया था, उसमें प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन था। यह सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड शरीर में प्रोटीन उत्पादन और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। प्रतिबंध सात जनवरी से लागू हुआ। जाधव इस अवधि के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित थी।

15 दिसंबर 2024 से उनके सभी परिणाम अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें इस अवधि के लिए सभी पुरस्कार, पदक, अंक, पुरस्कार और उपस्थिति राशि जमा करने होंगे। उन्होंने 25 फरवरी को एआईयू को एक ईमेल में उल्लंघन के आरोप का जवाब देते हुए कहा था, 'मुझे बेहद खेद है सर...मैं आपके फैसले का स्वागत करती हूं।' एआईयू ने कहा कि इस संवाद को लेकर उसकी समझ यह थी कि जाधव को सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी और वह निकाय से निर्णय से संतुष्ट थी। एआईयू ने कहा कि फिर भी जाधव को सूचित किया गया कि उनके पास यह स्वीकार करने के लिए तीन मार्च तक का समय है कि उन्होंने डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया है।

इसके बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने 28 फरवरी को उन्हें इसकी याद दिलाई। हालांकि, एआईयू को जाधव से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लिया था, जिसमें भारतीय महिला खिलाड़ियों में लिली दास, कविता यादव और प्रीति लांबा के पीछे चौथे स्थान पर रहीं थी। जाधव का 10,000 मीटर में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 35:44.26 और हाफ मैराथन में 1:20:21 है। 3,000 मीटर में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10:28.82 है।

सबालेंका को हराकर मीरा एंड्रीवा ने जीता इंडियन वेल्स का खिताब

कैलिफोर्निया। रूस की महिला वर्ग की टेनिस खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर इंडियन वेल्स का खिताब अपने नाम कर लिया हैं। आज यहां फाइनल में मुकाबले में एंड्रीवा ने इंडियन वेल्स दुनिया की नवंबर वन और तीन बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सबालेंका को 2-6 6-4 6-3 से हराया। यह एंड्रीवा का लगातार दूसरा डब्ल्यूटीए 1000 स्तर के टूर्नामेंट का खिताब है। एंड्रीवा 1998 में मार्टिना हिंगिस और सेरेना के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी सबसे कम उम्र की चैंपियन खिलाड़ी बन गई हैं। मैच के बाद ट्रॉफी उठाते हुए एंड्रीवा ने कहा कि मैं अंत तक लड़ने के लिए, हमेशा विश्वास रखने के लिए और कभी हार न मानने के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैंने आज खरगोश की तरह दौड़ने का प्रयास किया बस बने रहना वाकई मुश्किल था, इसलिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है।

आईपीएल उद्घाटन समारोह में श्रेया घोषाल, अभिनेत्री दिशा पटानी सहित कई सितारें कार्यक्रम पेश करेंगे

कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के उद्घाटन सत्र में इस बार बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल, अभिनेत्री दिशा पटानी और पंजाबी पॉप सिंगर करण औजला कार्यक्रम पेश करेंगे। इनके अलावा वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहं पिछले सत्र में अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, गायक सोनू निगम और एआर रहमान ने आईपीएल में कार्यक्रम पेश किया था। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने कहा कि आईपीएल उद्घाटन समारोह के लिए 25 मिनट का समय तय किया गया है, जिससे मैच की मनोरंजक शुरुआत हो सके। उन्होंने कलाकारों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है पर कहा कि यह एक भव्य आयोजन होगा। गांगुली ने कहा कि हम उद्घाटन समारोह का आयोजन करेंगे, हालांकि हमें अभी तक नहीं पता कि कौन-कौन प्रस्तुति देंगे। अभी तक लिखित पुष्टि नहीं हुई है पर निश्चित रूप से यह भव्य समारोह होगा। कुल मिलाकर कोलकाता के लोगों के लिए यह आईपीएल का एक खूबसूरत उद्घाटन समारोह होगा। आईपीएल 22 मार्च से शुरू होकर 25 मई को समाप्त होगा, जिसमें 13 शहरों में 74 मैच होंगे।

मेरे बारे में धारणायें बनाई गई, टाइपकास्ट किया गया लेकिन मुझे अपनी ताकत पता थी : श्रेयस

नई दिल्ली। उन्हें तथाकथित तकनीकी कमी को लेकर बनी धारणाओं से लड़ना पड़ा, उन्हें टाइपकास्ट किया गया और विश्व कप नायक बनने के कुछ महीनों के भीतर ही उनका अनुबंध रद्द कर दिया गया लेकिन श्रेयस अय्यर इन सबके बावजूद अडिग रहे और अपनी ईमानदारी और सुलझे हुए दिमाग पर भरोसा करके आगे बढ़े। इसका फल भी उन्हें मीठा ही मिला। पिछले कुछ समय में वह चौथे नंबर पर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बने और कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में मिली खिताबी जीत के बाद उन्हें 'मौन नायक' करार दिया। शॉर्ट गेंद के खिलाफ उनकी कमजोरी को लेकर पूछे जाने पर श्रेयस ने इंटरव्यू में कहा, 'शायद ऐसी धारणा बनाई गई थी या मुझे टाइपकास्ट किया गया। लेकिन मुझे हमेशा से अपनी ताकत, क्षमता पता थी और खुद पर भरोसा था।' पिछले 8 वनडे में उन्होंने चौथे नंबर पर 53 की औसत से रन बनाए हैं। उन्होंने कहा, 'खेल बदलता रहता है लिहाजा खिलाड़ी को लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करना होता है। मुझे खुशी है कि मैं सकारात्मक सोच के साथ खेल सका और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखा।' पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के दौरान उनकी कमर में चोट लगी और फिर उन्हें केंद्रीय अनुबंध गंवाना पड़ा चूंकि उस समय वह अपनी तत्कालीन आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अभ्यास कर रहे थे जबकि उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना था।

टीम का माहौल ऐसा हो, सभी अपनी बात रख सकें : ऋषभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 में इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की कप्तानी करने जा रहे ऋषभ पंत ने कहा कि वह टीम में ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे सभी खिलाड़ी अपनी बात रख सकें। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ ने कहा कि किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिये कि वह अपनी राय को व्यक्त नहीं कर सकता। उनका प्रयास एक खुला माहौल बनाना है। नये कप्तान ने कहा हम ऐसी जगह बनाना चाहते हैं, जहां लोग आकर अपनी बात कह सकें। यह एक बहुत ही सरल विचार है। इसे कहना आसान है पर अमल में लाना नहीं, क्योंकि इसके लिए हर व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है।

इस आक्रामक बल्लेबाज ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, यह काम केवल प्रबंधन ही नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की वजह से ही हम ऐसा माहौल बना पाते हैं क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि अगर आप अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं और उन्हें पर्याप्त भरोसा देते हैं, तो वे आपको किसी भी स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे इस समूह और प्रबंधन के पास अच्छा खास अनुभव है।

एलएसजी दो बार एलिमिनेटर में बाहर होने से पहले आईपीएल 2022 और 2023 सत्र के प्लेऑफ में पहुंची थी। आईपीएल 2024 में, एलएसजी अंक तालिका में सातवें स्थान पर रही। उन्होंने निकोलस पूरन, एडेन मार्करम और डेविड मिलर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से टीम के नए खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करने को भी कहा है।

कप्तान ने कहाकेवल अपने अनुभव को युवा खिलाड़ियों के साथ साझा करते रहें और उस अनुभव को इस समूह को हासिल करने दें। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो हम सभी सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बस एक दिन में एक बार इसे आगे बढ़ाएं, बस अपना 100 फीसद दें, टीम के हित को ध्यान में रखते हुए काम करे। उसमें ये सोचने की जरुरत नहीं कि हमारी टीम आपका समर्थन करेगी या नहीं। साथ ही कहा, मुझे लगता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। इसलिए हम सभी यहां एक साथ हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिये जिससे जब हम यहां से वापस जाएं, तो मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर खिलाड़ी ओर इंसान के रुप में याद किया जाये।

दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ को मेगा नीलामी में एलएसजी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ रकम देकर 27 करोड़ में खरीदा था। अब टीम आईपीएल 2025 सीजन का अपना पहला मैच 24 मार्च को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आसान और लाभकारी बिजनेस है मत्स्य पालन कॅरियर के हैं भरपूर अवसर

2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें।

भारत भर में मत्स्य पालन एक जाना पहचाना व्यवसाय रहा है। कृषि से इसको जोड़कर जरूर देखा जाता रहा है, किंतु हकीकत में यह काफी उन्नत और लाभकारी व्यवसाय है। वर्तमान में कोरोनावायरस के कारण बड़ी संख्या में गांवों की ओर लोगों का पलायन हुआ है। कई लोगों को रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि जमे जमाए व्यवसाय या फिर शहर में करने वाली नौकरी छूटने के बाद लोग गांव की ओर लौटे हैं। गांव में चूँकि अधिकतर लोगों के पास कम-अधिक जमीन होती ही है और ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन उन सबके लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है।

तालाब को ठीक से करें तैयार

अक्सर लोग किसी तालाब की खुदाई के बाद तुरंत ही मछली के बीज डाल देते हैं, लेकिन यह ठीक मेथड नहीं है। सबसे पहले तालाब की सफाई करने के बाद उसमें 200 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूने का छिड़काव जरूरी है। इसके अलावा महुए की खली और ब्लीचिंग पाउडर डालने से भी मछली पालन के लिए तालाब बेहतर कंडीशन में तैयार हो जाता है। यह सारा कार्य आप ठंड के मौसम में ही कर लें, ताकि ठंड का मौसम बीतते-बीतते मछली का बच्चा डालने योग्य आप का तालाब तैयार हो जाए। साथ ही तालाब में ढैंचा नामक घास भी बोया जाता है, ताकि बाद में वह खाद बन जाए और मछली पालन के लिए उपयुक्त रहे। यह तकरीबन 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब में बोया जाता है। साथ ही गोबर की खाद डालने से भी वनस्पति जल्दी उग जाती है। अगर समय पर तालाब में अच्छी घास नहीं होती है तो गोबर के साथ सुपर फास्फेट और यूरिया का घोल तालाब में डालना लाभकारी हो सकता है। हालांकि मछली का बीज डालने से काफी पहले ही यह कार्य करना चाहिए। मछली का बीज डालने के बाद खाद डालना खतरनाक हो सकता है। उपरोक्त कार्य करने के कम से कम 1 महीने बाद ही तालाब में पानी भरकर, ठंड का मौसम बीतने के बाद मछली का बीज डालें। साथ ही तालाब के पानी की गुणवत्ता और उस में ऑक्सीजन की ठीक मात्रा हो, इसके प्रति अतिरिक्त सजगता आवश्यक है।

मछलियों की ब्रीड पर खास ध्यान दें

अगर आपका तालाब ठीक ढंग से तैयार हो गया है, किंतु मछलियों के बीज आप सही ढंग से नहीं डालते हैं, तो आपके लिए यह लाभकारी नहीं रहेगा। मुख्य रूप से देशी और विदेशी ब्रीड की मछलियां लोग डालते हैं। इसमें देसी में रोहू, कतला, मृगल इत्यादि प्रचलित प्रजातियां हैं, तो विदेशियों में सिल्वर कॉर्प, ग्रास कार्प इत्यादि प्रमुख हैं। कई लोग जब बाहर से मछली लेकर आते हैं तो उसे एक दो परसेंट नमक के घोल में कुछ देरी के लिए रखते हैं, ताकि अगर मछली के बीज में कोई बीमारी है तो उसका असर कम हो जाए। हालांकि यह बहुत देर तक नहीं होना चाहिए और 2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें। अगर एक या दो मछली आपके तालाब में मर जाती हैं, तो उसे तत्काल निकाल कर बाहर करें समय-समय पर बीज की वृद्धि और उसकी जांच करना आपको नुकसान से बचा सकता है। मछलियों के लिए यूं तो किसी विशिष्ट चारे की जरूरत नहीं होती है, खासकर तब जब आप का तालाब पुराना हो गया हो, किंतु चावल का आटा और मूंगफली की खली इत्यादि मछलियों को तेजी से बढ़ाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त चारे की मात्रा मछलियों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इसके प्रति भी सजग रहें। ध्यान दें मछली का बीज सही क्वालिटी का हो, तो सही मात्रा में भी अवश्य हो, अन्यथा बाद में मछलियां ठीक ढंग से बढ़ेंगी नहीं।

मार्केट को समझना जरूरी है

अब जब आपके पास मछली के बीज तैयार हो जाते हैं तो आसपास की मार्केट का एक अध्ययन जरूर करें और देखें कि आपके आसपास किस तरह की मछलियों की खपत ज्यादा होती है। लोग आखिर क्या खरीदते हैं?
ऐसे में जब आप मछली मार्केट जाएंगे, तो एक ग्राहक बनकर मछलियों की ब्रीड से लेकर उसकी कीमत तक का पता कर सकते हैं। उसी अनुरूप आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर बड़ी मछलियों की खपत अधिक है, तब आपके तलाब में कम मछलियों का बीज रहना चाहिए, जबकि अगर छोटी मछलियों की खपत है तो तालाब में बीज अगर अधिक भी डालेंगे तो आपको फायदा ही होगा। कुल मिलाकर सही टाइम पर मछलियों को बेचना और सही व्यापारियों से संपर्क में रहना आपको लाभ दिला सकता है। कई बार मछली के व्यापारी आपके तालाब पर आकर खुद ही सारी मछलियां ले जाते हैं। हालांकि रेट में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप मछलियों को खुद भी मार्केट तक पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है। मतलब अगर आपके तालाब में कुछ मछलियां बड़ी हो गई हैं और कुछ मछलियां छोटी हैं, तो बड़ी मछलियों को या तो निकाल कर दूसरे तालाब में डालें या उन्हें मार्केट में भेज दें, क्योंकि बड़ी मछलियों का आहार अधिक होगा और वह छोटी मछलियों का चारा भी खा जाएंगी। इसलिए मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है ताकि मछलियों की ग्रोथ में एक निरंतरता रहे। साथ ही मछलियों में इंटरनल और एक्सटर्नल बीमारी के प्रति सजग रहें, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूँजी भारी नुक्सान में बदल गयी। इसके अलावा नई नई जानकारियां आप भिन्न माध्यमों से लेते रहें और अलग-अलग मछली पालकों के संपर्क में रहें। ऐसे में नई चीजें आपको पता चलेंगी।

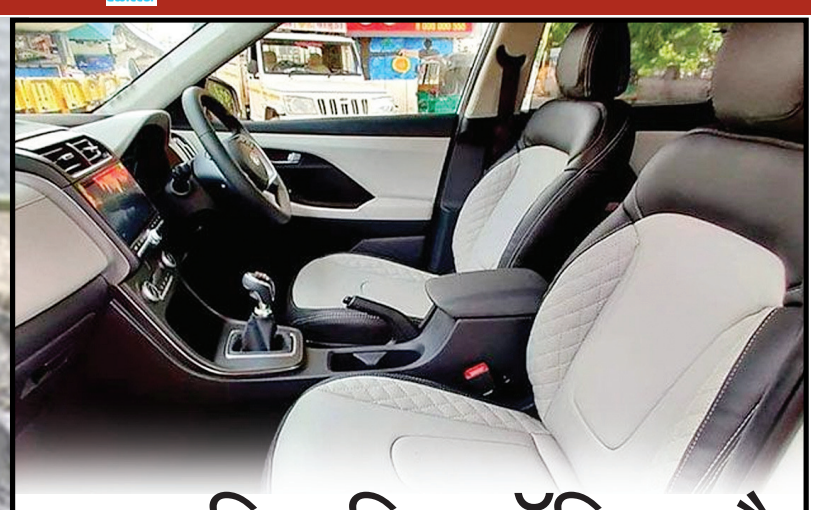

बहुत क्रिएटिव कॅरियर है कार एसेसरीज डिजाइनिंग

एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं।

कार एसेसरीज डिजाइनिंग एक ऐसा कॅरियर क्षेत्र है, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी होती है। लेकिन यह एक ऐसा क्रिएटिव कॅरियर क्षेत्र है, जिसमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है। यह एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर के काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह केवल कारों और इसके सामान के लिए पूरा करता है। कार एक्सेसरी डिजाइनर ऐसे व्यक्ति हैं जो कार एक्सेसरीज और पाट्र्स के लिए नए डिजाइन बनाते हैं। वे न केवल देखभाल की संरचना में सुधार करते हैं, बल्कि इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ाते हैं। ऐसा करते समय, एक कार एक्सेसरी डिजाइनर को वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और दिए गए मापदंडों के तहत काम करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस कॅरियर क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बता रहे हैं-

क्या होता है काम

एक कार एसेसरीज डिजाइनर तीन क्षेत्रों में से एक में काम करते हैं- इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग या कलर और ट्रिम डिजाइन। वे ड्राइंग, मॉडल और प्रोटोटाइप का उपयोग करके कार एक्सेसरी पाट्र्स, असेंबली और सिस्टम के ड्राफ्टिंग डिजाइन बनाते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि वे कार को विजुअली अधिक अपीलींग बनाएं।

स्किल्स - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि एक कार एसेसरीज डिजाइनर को हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जो वाहन में उपयोग होने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें ग्राहक की पूरी आवश्यकता को समझना चाहिए और डिजाइन और इसके उत्पादन के उपयोग के बारे में बड़े पैमाने पर शोध करना चाहिए। उनके भीतर कुछ अलग व हटकर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर व कार का तकनीकी ज्ञान उनके काम को अधिक आसान बनाता है।

योग्यता - एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज से उम्मीदवार अपनी डिग्री हासिल करता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

आमदनी - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व क्रिएटिविटी के आधार पर बढ़ती जाती है। हालांकि एक कार एसेसरीज डिजाइनर की एवरेज सालाना सैलरी सात से आठ लाख के बीच होती है।

प्रमुख संस्थान

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नवी मुंबई
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
एरिना एनिमेशन, बैंगलोर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई
वीआईडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली
वाईएमसीए इंस्टीट्यूट फॉर ऑफिस मैनेजमेंट, नई दिल्ली

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में कॅरियर बनाने के लिए क्या करें?

कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
ऑपरेशन्स मैनेजमेंट आपके भविष्य के कॅरियर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों के निवेश की एक लंबी प्रक्रिया है। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया विभिन्न अवधारणाओं को अपनाती है, जैसे- आत्म-जागरूकता, कॅरियर विकास योजना और करियर अन्वेषण, जीवन भर सीखने की क्षमता और नेटवर्किंग। कॅरियर में अर्ध-कुशल से लेकर कुशल और अर्ध पेशेवर से पेशेवर तक के सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। हालांकि, पूरी करियर प्रबंधन प्रक्रिया परिभाषित लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना पर ही आधारित होती है।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य

सामान्य शब्दों में परिचालन प्रबंधन किसी संगठन के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक कुशल तरीके से सामग्रियों और श्रम को वांछित वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करने से संबंधित है। यह उपलब्ध संसाधनों की खरीद और उपयोग करके उत्पादन को अधिकतम करता है, जिसमें कच्चे माल, उपकरण, प्रौद्योगिकी, सूचना और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उत्पादन की प्रक्रिया की योजना, डिजाइनिंग, आयोजन, नियंत्रण और अनुकूलन के साथ इसका अधिक सम्बन्ध होता है। संचालन प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि एक इकाई कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक इनपुट को आउटपुट में कैसे बदल देती है। यह स्पष्ट है कि संचालन प्रबंधन डिलीवरी ओरिएंटेड होता है। हालांकि, संचालन प्रबंधन को लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के समान नहीं माना जाना चाहिए। संचालन प्रबंधन व्यापक है और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन इसका एक हिस्सा है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन किसी अभियान, योजना, परियोजना या रणनीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों, सामग्री और अन्य संसाधनों की खरीद, निष्पादन और नियंत्रण की योजना बनाता है। विनिर्माण और सेवा संगठनों दोनों को ही संचालन प्रबंधन के कार्य की आवश्यकता होती है, जो एक प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक कवर करता है। सदियों से विनिर्माण उद्योग फल-फूल रहे हैं। अब सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ परिचालन प्रबंधकों के लिए अवसर कई गुना बढ़ गए हैं।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए क्या करें?

अन्य विषयों की तरह प्रबंधन शिक्षा में भी कई विषय होते हैं। प्रबंधन के छात्रों को प्रबंधन के सभी प्रमुख विषयों के अवलोकन के साथ संयुक्त रूप से सामान्य प्रबंधन के तहत विषयों और सिद्धांतों से गुजरना पड़ता है। हालांकि, दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में प्रबंधन की एक विशेष शाखा में विशेषज्ञता का प्रावधान है। प्रबंधन की प्रसिद्ध शाखाओं में विपणन, वित्त, मानव संसाधन आदि शामिल हैं। संचालन प्रबंधन के लिए आपको निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है :

- नेतृत्व
- नीति, योजना और रणनीति की समझ
- नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने, लागू करने और समीक्षा करने की क्षमता
- बजट, रिपोर्टिंग, योजना और लेखा परीक्षा की देखरेख करने की क्षमता
- आवश्यक कानूनी और नियामक दस्तावेजों की समझ

इसके साथ-साथ आपको इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है :

- सुनिश्चित करें कि आप सही मेट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं
- मुख्य समस्याओं को पहचानने के लिए हमेशा डेटा का उपयोग करें
- नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अप-टू-डेट रहने में विश्वास करें
- स्वचालन से पहले प्रक्रियाओं पर ध्यान दें
- ध्यान से लोगों के साथ कम्यूनिकेट करें

ऑपरेशन्स मैनेजर बनने के लिए आवश्यकता योग्यता

संचालन प्रबंधक के संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की डिग्री के साथ, छात्रों को ज्ञान और विपणन योग्य कौशल विकसित करना होता है, जिसे वे अपने कॅरियर के दौरान बना सकते हैं। इसके अलावा, एक संचालन प्रबंधक होने के लिए, किसी के पास मजबूत नेतृत्व और पारस्परिक कौशल, शानदार संचार और ग्राहक की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। संचालन प्रबंधक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है :

विषय संयोजन- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम
उम्मीदवारों के पास 10 + 2 + 3 प्रणाली के माध्यम से योग्यता और किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए
उम्मीदवारों के पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए (ऑपरेशंस) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री का भी बहुत महत्त्व होता है

ऑपरेशन्स मैनेजर के जॉब रोल्स

सप्लाई चेन मैनेजर
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर
प्लांट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर
परचेस मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर
इन्वेंटरी कण्ट्रोल मैनेजर

रोजगार के अवसर

एक ऑपरेशन मैनेजर के रूप में इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर होते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संचालन प्रबंधकों के लिए बहुत स्कोप है। कुछ शीर्ष क्षेत्र इस प्रकार हैं :

स्वास्थ्य कॉर्पोरेट व्यवसाय
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हॉस्पिटैलिटी
विनिर्माण और खुदरा वित्तीय संस्थाए
बीमा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी
ई-कॉमर्स वेयरहाउसिंग
निर्माण सलाहकारी फर्में

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सीमा हैदर और सचिन के घर आया नया मेहमान

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर पांचवी बार मां बन गई है। यह बच्चा सीमा और सचिम मीणा का है। हैदर ने ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे बच्ची को दिया जन्म। करीब दो साल पहले चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और नेपाल के रास्ते सीमा भारत आई थी। हालांकि उसे अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुई थी। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और सीमा बच्चों सहित अपने प्रेमी सचिन के पास रहन के लिए आ गई।सीमा और सचिन ने पिछले साल दिसंबर के महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सीमा के गर्भवती होनी की जानकारी दी गई थी। दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। वीडियो में हैदर प्रेग्नेंसी किट दिखाते हुए सचिन को पिता बनने की खुशखबरी दे रही थीं। जिसके बाद सचिन सीमा को गले लगा लेता है। तब सीमा ने बताया था कि वह सात महीने की गर्भवती है। जल्द ही उनके घर किलकारी गूंजने वाली है।

शिरडी एयरपोर्ट परिसर में खुलेआम घूम रहे तेंदुए, भयभीत हैं यात्री और स्टाफ

शिरडी (एजेंसी)। महाराष्ट्र के शिरडी एयरपोर्ट इलाके में एक मादा तेंदुए ने दो शावकों को जन्म दिया है। इसके चलते एयरपोर्ट स्टाफ में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग ने एयरपोर्ट के अंदर पिंजरे लगा दिए हैं और तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एयरपोर्ट परिसर में खुलेआम घूम रहे तेंदुए से यात्री और स्टाफ भयभीत हैं। खबर है कि शिरडी एयरपोर्ट इलाके में दो शावकों के साथ घूम रही मादा तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। वन विभाग ने कहा है कि ये वीडियो सही हैं। जानकारी मिलने के बाद एयरपोर्ट क्षेत्र में चार पिंजरे लगाए गए हैं। बता दें कि वन विभाग ने कुछ महीने पहले एक नर तेंदुए को पकड़ने में सफलता पाई थी। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही मादा तेंदुए और उसके दो शावकों को भी पकड़ लिया जाएगा। मालूम हो कि शिरडी एयरपोर्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ और झाड़ियां होने के कारण इस क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही बढ़ गई है। वन विभाग पिछले कुछ महीनों से मादा तेंदुए और उसके शावकों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तेंदुए की आवाजाही के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों और स्थानीय निवासी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक मादा तेंदुआ एयरपोर्ट परिसर के अंदर चली गई और उसने शावकों को जन्म दिया। तब तक प्रशासन क्या कर रहा था। एयरपोर्ट क्षेत्र में पेड़ों और झाड़ियों के कारण यह देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। तेंदुए एयरपोर्ट के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ में बाधा आ सकती है। साथ ही तेंदुआ एयरपोर्ट क्षेत्र में यात्रियों पर भी हमला कर सकते हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई टली

वाराणसी (एजेंसी)। सिखों पर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि राहुल गांधी के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)की अदालत में वकालतनामा दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 14 अप्रैल तय की है। तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की है। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सिखों के लिए भारत में अच्छा माहौल नहीं है। ऐसे बयान से देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कर रहे हैं।

24 दलितों की सामूहिक हत्याकाण्ड मामले में 44 साल बाद तीन को फांसी की सजा

मैनपुरी (एजेंसी)। उप्र के फिरोजाबाद के जसराना के गांव दिहुली में 18 नवंबर 1981 को हुई 24 दलितों की सामूहिक हत्या में मंगलवार को कोर्ट ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो दोषियों पर दो-दो लाख और एक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट से आदेश होने के बाद पुलिस तीनों को जिला कारागार मैनपुरी ले गई। वहां उन्हें दाखिल किया गया। एडीजे विशेष डकैती इंदिरा सिंह की अदालत में सुबह 11.30 बजे दोषी कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को मैनपुरी जिला कारागार से भारी सुरक्षा के बीच लाकर पेश किया गया। इनकी पेशी के बाद 12.30 बजे करीब फिर से इनको दीवानी की अदालत में भेज दिया गया। लंच बाद कोर्ट से फिर इनकी पुकार हुई। दोपहर तीन बजे तीनों दोषियों को फिर से पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से रोहित शुक्ला ने तमाम दलीलें पेश करते हुए नरसंहार के साक्ष्यों और गवाही का हवाला देते हुए फांसी की मांग की। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर उस भयावह नरसंहार के दोषी कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई। कप्तान सिंह, रामसेवक को दो-दो लाख और रामपाल को एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया। सजा सुनते ही तीनों के चेहरों पर मायूसी छा गई। यह रोने लगे। कोर्ट के बाहर इनके परिजन भी मौजूद थे, वह भी रोने लगे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें जेल ले जाकर दाखिल कर दिया।

मोमोज बनाने वाली एक फैक्ट्री के फिज में कुत्ते का सिर मिला, पुलिस जांच में जुटी , पंजाब के मोहाली का मामला

मोहाली(एजेंसी)। पंजाब के मोहाली में नगर निगम की मेडिकल टीम ने चिकन की दुकानों पर छापेमारी कर करीब 60 किलो बदबूदार फ्रोजन चिकन जब्त किया। साथ ही टीम ने चिकन को नष्ट कर दुकानों का चालान काटा है। दावा है कि इस दौरान मोमोज बनाने वाली एक फैक्ट्री के फिज में कुत्ते का सिर भी मिला है। मोहाली के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. अमृत वारिंग ने कहा कि फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। वितरण के लिए मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने वाली फैक्ट्री की जांच हो रही है, ताकि पता लग सके कि कुत्ते का मांस इस्तेमाल हुआ था या नहीं।

नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में होगी एंट्री, जेडीयू नेता दे रहे ट्रेनिंग

पटना (एजेंसी)। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार सार्वजनिक रूप से 8 जनवरी को सामने आए थे। वे अपने पिता के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि देने अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे थे। मीडिया से वे पहली बार रुबरु हुए थे। वे जितना बोले, उससे यही लगा कि उन्हें जितना बोलने के लिए कहा गया था, उतना ही उन्होंने कहा। नपे-तुले शब्दों और पोलिटिकल अंदाज में उन्होंने पिता के कार्यों के लिए उन्हें वोट देने की अपील की। उसी दिन से यह बात चल पड़ी की निशांत राजनीति में एंट्री करने वाले हैं।

निशांत पिता नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास पर लोगों से मिलते रहे। नीतीश की ही तरह वे जेडीयू नेताओं और सरकारी अधिकारियों से मिले। इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े नेताओं को भी उनसे मिलना औपचारिकता से ज्यादा जरुरी लगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी ने तो निशांत को ऐसा भाव दिया, जैसे वे जेडीयू के सीनियर लीडर हों।

निशांत की 50 के आसपास है। निशांत मौजूदा सीएम के बेटे हैं और तेजस्वी पूर्व मुख्यमंत्री के। चिराग पासवान भी पिता की विरासत ही संभाल रहे हैं। 10 साल के राजनीतिक करियर में तेजस्वी डिप्टी सीएम दो बार बन गए तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए। लगता है कि निशांत ने अब जिद छोड़ दी है। वे भी दूसरे नेता पुत्रों की तरह राजनीति में आना चाहते हैं। उम्र के हिसाब से निशांत की समझ तो बढ़ी ही होगी। फिर भी पहली बार राजनीति में जगह बनाने के लिए निशांत को राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत होगी। उन्हें जेडीयू के कुछ नेता राजनीति की बारीकियां समझा रहे हैं।

अब लगता है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी जिद छोड़ दी है। वे तो वंशवादी राजनीति के कट्टर विरोधी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने जीते जी परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में आने से रोका। नीतीश कुमार दूसरे समाजवादियों की तरह ही इस बात के पक्षधर रहे हैं कि रानी की कोख से जन्मा व्यक्ति ही राजा नहीं बनेगा. लालू यादव की वंशवादी राजनीति पर नीतीश के तेवर हाल तक तल्ख रहे हैं. जब तक निशांत की एंट्री की औपतारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक यही मान कर चलना होगा कि नीतीश कुमार की वंशवादी राजनीति पर धारणा बदली नहीं है।

नीतीश कुमार जानते हैं कि पिछली बार जैसी ही अगर जेडीयू की खराब स्थिति रही तब भी वे सब पर भारी पड़ेंगे। बीजेपी और जेडीयू को पिछली बार जितनी ही सीटें मिली तब भी नीतीश को खेल करने का मौका मिल जाएगा। आरजेडी और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जेडीयू पर ही निर्भरता रहेगी। यानी नीतीश किंगमेकर की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी उन्हें आरजेडी की ओर मुखातिब होने नहीं देना चाहेगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी द्वारा सीएम फेस घोषित न करने के बावजूद नीतीश को कोई बेचैनी नहीं है।

रिपोर्ट में खुलासा : देश के 45 फीसदी विधायकों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले

-आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 138 तो सिक्किम में है सिर्फ एक

नई दिल्ली, । चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक एनजीओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के 45 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का विशेषण किया जिसमें आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 (79फीसदी) विधायकों ने जबकि, सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक (3फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 (86फीसदी) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। 24 विधायकों के हलफनामे का एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका, जबकि विधानसभाओं में सात सीटें खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं, 226 पर धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर 376 और 376 (2)(एन) के तहत रेप का आरोप है। धारा 376 (2)(एन) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है।

मणिपुर में हालात हो रहे सामान्य, 7,000 नए आवास मंजूर किए गए

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। मणिपुर में हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहां हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। हिंसा में बेघर हुए लोगों के लिए करीब 7,000 नए आवास मंजूर कर दिए गए हैं। राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक फंड दिया जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था के लिए सेना व असम राइफल्स की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 286 कंपनियों को राज्य पुलिस के साथ मणिपुर में तैनात किया गया है। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी।

उन्होंने बताया कि मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नेशनल हाईवे पर सुरक्षित और सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि करीब 60 हजार लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। वहीं करीब 7000 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष पैकेज के तहत 400 करोड़ रुपए रिलीफ कैंप ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर हो गए लोगों के लिए सात हजार घरों को मंजूरी दी गई है। मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी, मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी और सरकारी आवास योजनाएं उपलब्ध की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को नियंत्रित और बेहतर करने के लिए राज्य में लगातार काम हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मणिपुर में रिलीफ के लिए सौ करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि एनडीआरएफ और 68 करोड़ रुपए की राशि एसडीआरएफ के तहत रखी गई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर राज्य के लिए 500 करोड़ का आपातकालीन फंड बनाया गया है। यह फंड राज्य के लिए है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस धन राशि का उपयोग किया जा सके।

सत्ता में बैठे लोगों के धन शोधन में शामिल होने से शासन पर जनता का विश्वास खत्म हुआ

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जताई नाराजगी

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और इसमें सत्ता में बैठे लोगों के शामिल होने पर नाराजगी जताई है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मामलों में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की याचिका खारिज कर दिया गया और कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के धन शोधन में शामिल होने से शासन में जनता का विश्वास खत्म हुआ है और वित्तीय संस्थानों में प्रणालीगत कमजोरियां पैदा हुई हैं।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें प्रदीप शर्मा ने गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के कई मामलों की शुरूआती जांच का अनुरोध किया था। मनी लॉन्ड्रिंग, एक ऐसी वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी अपनी सम्पत्ति के अवैध स्रोत को छिपाते हैं। इस धोखाधड़ी का मकसद कालेधन को सरकार और कानूनी एजेंसियों की नजरों से छिपाना होता है ताकि इसे बिना किसी शक के इस्तेमाल किया जा सके।

मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया के ज्यादातर देशों में एक गंभीर अपराध है। भारत में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में कहा कि धन शोधन के दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत कृत्यों के संदर्भ में, बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी काफी नुकसान होता है।

युगल पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में कथित अपराधों का अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अवैध वित्तीय लेन-देन राज्य को वैध राजस्व से वंचित करते हैं, बाजार की

अखंडता को प्रभावित करते हैं और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। सत्ता में बैठे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कृत्य शासन में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं और वित्तीय संस्थानों के अंदर प्रणालीगत कमजोरियों को जन्म देते हैं।

अमेरिकी एनएसए तुलसी गबार्ड ने कहा, ट्रंप और मोदी शांति के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह शांति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारत दौरे पर आईं तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह पीएम मोदी भी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी एनएसए गबार्ड ने रायसीना डायलॉग 2025 में स्पष्ट किया कि 'अमेरिका फर्स्ट' का मतलब अमेरिका इकलौता नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए को अक्सर गलत समझा जाता है। तुलसी गबार्ड ने कहा, यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट का आह्वान कर रहे हैं तब वे अलगाववादी हैं। यह आरोप एक गहरी गलतफहमी या गलत धारणा को दिखाता है कि दूसरे देशों के साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका संघर्ष है। वे एक शांतिदूत और एकजुट करने वाले नेता के रूप में अपनी विरासत चाहते हैं। तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प एक शांतिदूत और एकजुट करने वाले नेता के रूप में अपनी विरासत छोड़ना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य अपने नेतृत्व को सबसे अच्छी और समय पर खुफिया जानकारी प्रदान करना है। जब पीएम मोदी वाशिंगटन में थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि साइबर सुरक्षा साधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए हमारे सुरक्षा हितों को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए पीएम मोदी का वॉशिंगटन का शुरुआती दौरा एक निजी दोस्ती थी।

तेलंगाना में बिल पास: पिछड़ों को मिलेगा 42 फीसदी आरक्षण, भाजपा ने किया समर्थन

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना में पहले जाति आधारित गणना की गई इसके बाद पिछड़ी जातियों को 42 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक भी पास कर दिया गया। विधेयक के मुताबिक पिछड़ी जातियों को ना केवल सरकारी नौकरियों बल्कि शिक्षण संस्थानों और शहरी और ग्रामीण निकाय के चुनावों में भी इतना आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक का सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा विपक्षी बीआरएस और बीजेपी ने भी समर्थन कर कर दिया है।

बीआरएस नेता हरीश राव ने कहा, हम पिछड़ों के लिए 42 फीसदी के आरक्षण का बिना शर्त समर्थन करते हैं। पार्टी के नेता गांगुला कमलाकर ने कहा, देश में पिछड़ी जातियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम इस आरक्षण के लिए करेंगे। बीजेपी की पायल शंकर ने कहा, कांग्रेस की वजह से ओबीसी आरक्षण में देरी हुई। हम बिल का समर्थन करते हैं लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कास्ट सर्वे वैज्ञानिक तरीके से करवाया गया या नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से आरक्षण लागू किया जा रहा है, वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण मुस्लिमों के लिए नहीं है बल्कि मुस्लिमों में पिछड़ी जातियों के लिए है। कांग्रेस को धर्म के आधार पर देश को बांटना छोड़ देना चाहिए।

विधानसभा में इससे संबंधित तीन विधेयक पेश किए गए थे। एक में उपजातियों को भी आरक्षण देने के प्रावधान है। तेलंगाना की सरकर ने कास्ट सर्वे करवाया था जिसमें पता चला था कि 56.33 फीसदी पिछड़ी जातियां हैं। इसमें मुस्लिम समुदाय की भी जातियां शामिल थीं। बिल पेश करते हुए पिछड़ी जाति कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा, तेलंगाना विधासनभा से एक संदेश जाना चाहिए कि हम सब पिछड़ी जातियों के लिए 42 फीसदी रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं। ये जातियां देश का आधार बन गई हैं।विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 42 फीसदी रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन आरक्षण विधेयकों का सभी पार्टियां समर्थन दे रही हैं। यह देश को बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन कर रहे हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सीएम ने कहा कि 42 फीसदी आरक्षण का वादा पूरा करने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे।उन्होंने कहा, सभी पार्टियों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आरक्षण की सीमा बढ़ाने की अपील करनी चाहिए। इस आरक्षण को तभी लागू किया जा सकता है जब केंद्र सरकार संविधान की नौवीं सूची में इसे शामिल करेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बांदी संजय कुमार से भी अपील की कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय दिलवाएं। वहीं इस मामले को राहुल गांधी संसद में भी उठा सकते हैं।

रेल मंत्री वैष्णव ने लालू और ममता की खोली पोल, तब हर दिन एक या दो रेल दुर्घटनाएं होती थीं

1 किलोमीटर यात्रा की लागत करीब 1.4 रुपये, ले रहे सिर्फ 73 पैसे

नई दिल्ली (एजेंसी)। रेल दुर्घटनाओं की हालिया घटनाओं के बाद विपक्ष की ओर से किए गए हमलों के बीच राज्यसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए हर दिन एक या दो रेल दुर्घटनाएं होती थीं जबकि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण संख्या घटकर प्रति वर्ष केवल 30 दुर्घटनाओं तक रह गई है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जब राजद सुप्रीमो लालू यादव रेल मंत्री थे (2005-06) तब कुल 698 दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुई थीं। वहीं ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के दौरान 395 दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, पहले औसतन प्रतिदिन एक दुर्घटना होती थी लेकिन अब यह संख्या घटकर प्रति वर्ष सिर्फ 30 हो गई है। यदि हम 43 रेल दुर्घटनाओं को भी शामिल करें तब कुल दुर्घटनाएं 73 होती हैं यानी पहले जो आंकड़ा करीब 700 था वह अब 80 से भी कम हो गया है जोकि 90 प्रतिशत रेल हादसों की की कमी को दिखाता है।

वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान अपनी कार्यकुशलता को साबित किया है और अब यात्री और माल ढुलाई दोनों में वृद्धि देखी जा रही है।

उन्होंने राज्यसभा को संबोधित कर बताया कि एक किलोमीटर यात्रा की लागत करीब 1.4 रुपये है, लेकिन यात्रियों से सिर्फ 73 पैसे लेते हैं। इस साल भारतीय रेलवे ने 1,400 इंजनों का उत्पादन किया है जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। उन्होंने कहा कि जनरल कोचों की संख्या एसी कोचों की तुलना में 2.5 गुना बढ़ाई जा रही है। साथ ही मौजूदा उत्पादन योजना के तहत 17,000 नॉन-एसी कोचों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।

घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजें भी बढ़ा सकती हैं कैंसर का खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। जानलेवा बीमारी कैंसर के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजें भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं। ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, तो इनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल अब आम हो चुका है, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि इन बर्तनों की कोटिंग में मौजूद परफ्लूरोऑक्टेनिक एसिड और अन्य टॉक्सिक पदार्थ कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसलिए स्टील या लोहे के बर्तनों का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित है। इसी तरह, प्लास्टिक की बोतलों में बिस्फेनॉल और फटालेट्स नामक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर जाकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

कई शोध बताते हैं कि प्लास्टिक के बारीक कण पानी के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसलिए, प्लास्टिक की बोतलों के बजाय कांच या तांबे की बोतलों का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। कई लोग रोटियां और अन्य खाने की चीजें रखने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद अधिक मात्रा में एल्युमिनियम लंबे समय तक शरीर में जमा होकर ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। इसी तरह, किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक कंटेनर भी कैंसर कारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद बीपीए केमिकल खाद्य पदार्थों में मिलकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी जगह स्टील या सिलिकॉन के कंटेनर का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रिफाइंड ऑयल का अधिक इस्तेमाल भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

उच्च तापमान पर गर्म होने पर यह टूटकर हानिकारक केमिकल्स उत्पन्न करता है, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए सरसों, नारियल या जैतून के तेल का उपयोग करना सेहत के लिए अधिक फायदेमंद है। इसके अलावा, घरों में इस्तेमाल होने वाली सेंटेड कैंडल्स से निकलने वाले केमिकल्स, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड से निकलने वाले जहरीले तत्व भी कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए, इन चीजों से बचाव ही सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का आधार है। बता दें कि विज्ञान ने आज भले ही कई बीमारियों का इलाज खोज लिया हो, लेकिन कैंसर के लिए अब तक कोई फुलप्रूफ इलाज विकसित नहीं हो सका है। यह बीमारी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले रही है।

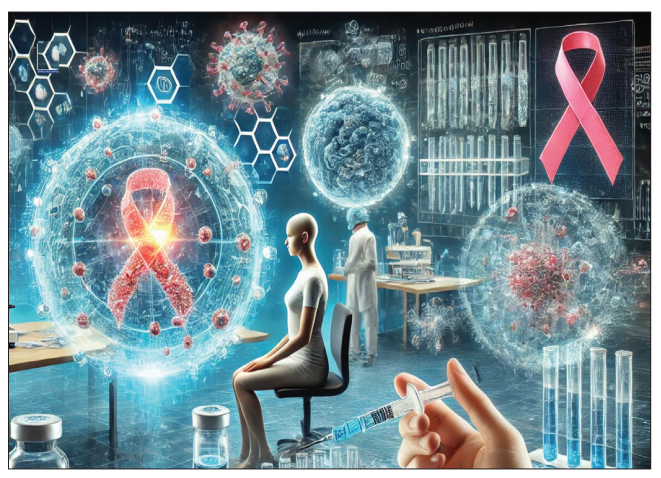

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

एक महीने से अधिक समय बाद वेटिकन ने पोप की पहली तस्वीर जारी की

रोम, एजेंसी। वेटिकन ने रविवार को एक महीने से ज्यादा समय बाद पोप की पहली तस्वीर जारी की। फोटो में फ्रांसिस अस्पताल के चैपल में सामूहिक प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर पीछे से ली गई है। पोप फ्रांसिस बैंगनी रंग का स्टोल पहने हुए एक वेदी के सामने व्हीलचेयर पर बैठे दिख रहे हैं। वेटिकन ने कहा, वे अन्य पादरियों के साथ सामूहिक प्रार्थना समारोह में भाग लेने गए थे। फोटो में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। पोप की पहली तस्वीर है, जब उन्हें 14 फरवरी को ब्रोंकाइटिस की गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

चीन ने पाकिस्तान को सौंपी एक और पनडुब्बी

बीजिंग, एजेंसी। चीन ने पाकिस्तान को एक और अत्याधुनिक पनडुब्बी सौंपी है। इसमें उन्नत हथियार व सेंसर लगे हुए हैं। चीन पाकिस्तान की नौसैन्य ताकत बढ़ाकर अरब सागर व हिंद सागर में दबदबा बढ़ाना चाहता है। उसने हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी को वुहान शहर में लॉन्च किया। इसी श्रेणी की एक पनडुब्बी पहले ही वह पाकिस्तान को दे चुका है।

सोनिक हथियार इस्तेमाल करने के आरोपों से सर्बियाई सरकार का इनकार

बेलग्रेड , एजेंसी। सर्बियाई अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर सैन्य स्तर के सोनिक हथियार के इस्तेमाल से इनकार किया है। दरअसल सर्बिया में शनिवार को राजधानी बेलग्रेड में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे, जो रेल हादसे को लेकर सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने सैन्य स्तर के सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया। इस हथियार के इस्तेमाल से लोगों की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वे इसकी शिकायत यूरोप की मानवाधिकार अदालत में करेंगे। हालांकि अब सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है।

यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुटे कनाडा के नए पीएम

ओटावा, एजेंसी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सोमवार को पेरिस और लंदन के दौरे पर रवाना हुए। कनाडा के प्रधानमंत्री का यह दौरा कनाडा के यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है। मार्क कॉर्नी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में तनाव चल रहा है। मार्क कार्नी ने शुक्रवार को अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा कि कनाडा का आधार तीन लोग हैं, जिनमें फ्रेंच, इंग्लिश और मूल निवासी शामिल हैं। कनाडा आधारभूत रूप से अमेरिका से अलग है और यह कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। अब मार्क कार्नी के लंदन और पेरिस के दौरे को भी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संबंधों को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

फिर भूकंप के झटकों से कांपी धरती, चीन और इथियोपिया में आए 4 से 6 तीव्रता के भूकंप

बीजिंग, एजेंसी। आज फिर भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। आज सुबह भारत के पड़ोसी देश चीन में भूकंप आया। इसके अलावा देर रात इथियोपिया में भी भूकंप आया और उसके बाद लगातार झटके आ रहे हैं, जिनकी तीव्रता भी रिक्टर पैमाने पर अलग-अलग है। चीन में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र चीन के किंगहाई शहर के पास धरती के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में पाया गया। इथियोपिया में पहला भूकंप देर रात करीब 12:23 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। इसके बाद 4.3 और 5.1 तीव्रता के झटके भी आये। लोगों को लगातार भूकंप के झटकों से जूझना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक दोनों देशों में भूकंप के कारण किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दोनों देशों में भूकंप की पुष्टि की है।

अमेरिका ने अल सल्वाडोर के साथ समझौता किया

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रम्प ने दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अल सल्वाडोर से समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका के हिंसक अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को वहां की जेलों में रखा जाएगा। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया।

सीरिया के तटीय शहर लताकिया में धमाका, 16 लोगों की मौत

लताकिया, एजेंसी। सीरिया के तटीय शहर लताकिया में हुए एक विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई। देश की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक धमाके के बाद एक इमारत ढह गई, जिसमें 16 लोग मारे गए, जबकि 18 घायल हुए। व्हाइट हेल्मेट्स के नाम से मशहूर पैरामेडिक समूह ने बताया कि मलबे के नीचे से 16 शव बरामद किए गए मृतकों में पांच महिलाएं और पांच बच्चे शामिल थे।

प्रशासन ने कोर्ट की रोक बावजूद लोगों को किया निर्वासित, अफसर बोले- जब फैसला आया उड़ानें हवा में थीं

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रम्प प्रशासन ने अदालत की ओर से रोक लगाने के बावजूद सैकड़ों अप्रवासियों को अल साल्वाडोर भेज दिया। दूसरी ओर, एक संघीय न्यायाधीश ने वेनेजुएला के गिरोह के सदस्यों को लक्षित करने वाले 18वीं सदी के युद्धकालीन घोषणापत्र के तहत निर्वासन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने रविवार बताया कि जिस वक्त फैसला आया उड़ानें हवा में थीं।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स ई. बोसबर्ग ने शनिवार को एक आदेश जारी कर निर्वासन को अस्थायी रूप से रोक दिया, लेकिन वकीलों ने उन्हें बताया कि पहले से ही दो विमान अप्रवासियों को लेकर हवा में हैं - एक अल साल्वाडोर जा रहा है, दूसरा होंडुरास जा रहा है। बोसबर्ग ने मौखिक रूप से विमानों को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने अपने लिखित आदेश में निर्देश शामिल नहीं किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार को एक बयान में इस बारे में अटकलों का जवाब दिया कि क्या प्रशासन अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रहा है? उन्होंने कहा, प्रशासन ने अदालती आदेश का पालन करने से इनकार नहीं किया। यह आदेश, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं था, आतंकवादी टीडीए एलियंस को अमेरिकी क्षेत्र से पहले ही हटा दिए जाने के बाद जारी किया गया था। टीडीए एलियंस का पूरा

नाम ट्रैन डे अरागुआ गिरोह है, जिसे ट्रम्प ने शनिवार को जारी अपने असामान्य उद्घोषणा में निशाना बनाया था। रविवार को अदालत में दायर एक दस्तावेज में न्याय विभाग, जिसने बोसबर्ग के निर्णय के विरुद्ध अपील की है, ने कहा कि यदि निर्णय को पलटा नहीं जाता है तो वह आगे निर्वासन के लिए ट्रम्प द्वारा की गई घोषणा का उपयोग नहीं करेंगे।

ओह...बहुत देर हो गई, सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, जिन्होंने अपने देश की जेलों में 6 मिलियन की लागत से एक साल के लिए लगभग 300 अप्रवासियों को रखने पर सहमति व्यक्त की, ने बोसबर्ग के फैसले के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। उस पोस्ट को व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने फिर से प्रसारित किया।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जिन्होंने बुकेले के साथ अप्रवासियों को आवास देने के लिए पहले एक समझौता किया था, ने साइट पर पोस्ट किया, हमने ट्रेन डी अरागुआ के 250 से अधिक विदेशी दुश्मन सदस्यों को भेजा है, जिन्हें अल साल्वाडोर ने उचित मूल्य पर अपनी बहुत अच्छी जेलों में रखने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे हमारे करदाताओं के पैसे भी बचेंगे। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के प्रोफेसर स्टीव व्लाडेक ने कहा कि विमानों को वापस मोड़ने का बोसबर्ग का मौखिक निर्देश तकनीकी रूप से उनके अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं था, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने स्पष्ट रूप से इसकी भावना का उल्लंघन किया है। व्लाडेक ने कहा, इससे भविष्य की अदालतों को अपने आदेशों में अति विशिष्ट होने तथा सरकार को कोई छूट न देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रम्प द्वारा 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम की घोषणा के बाद आप्रवासियों को निर्वासित कर दिया गया था, जिसका उपयोग अमेरिकी इतिहास में केवल तीन बार किया गया है।

प्रधानमंत्री ओली का राजशाही समर्थकों पर कटाक्ष-नेपाल के लोकतंत्र में 'रिवर्स गियर' नहीं

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने राजशाही समर्थक समूहों पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहा कि लोकतंत्र एक 'राजमार्ग' की तरह है, जिसमें कोई 'रिवर्स गियर' नहीं होता, केवल कभी-कभार तीखे मोड़ के कारण क्षणिक रूप से गति धीमी करनी पड़ती है। उन्होंने इसके साथ ही आगे बढ़ने पर जोर दिया। पिछले हफ्ते पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के सैकड़ों समर्थकों ने राजधानी में उनके स्वागत में रैली निकाली थी। ज्ञानेंद्र (77) पिछले सप्ताह रविवार को जैसे ही देश के विभिन्न भागों में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर पोखरा से काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, समर्थकों ने उनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस रैली का उद्देश्य नेपाल में राजशाही की पुनः स्थापना के प्रति समर्थन प्रदर्शित करना था। ओली ने रविवार को यहां महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए राजशाही समर्थक समूहों द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ''हमें हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है। पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। रिवर्स गियर (वाहन को पीछे ले जाने में सक्षम) कभी-कभी तब लगाया जाता है जब सड़क पर तीखे मोड़ हों। राजमार्ग पर कोई 'बैक गियर' नहीं है और लोकतंत्र हमारा राजमार्ग है।'' पूर्व राजा के समर्थक गत कई दिनों से काठमांडू और पोखरा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकाल रहे हैं और 2008 में समाप्त की गई राजशाही को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राजतंत्र समर्थक फरवरी में लोकतंत्र दिवस के बाद तब सक्रिय हुए जब ज्ञानेन्द्र ने कहा था, ''समय आ गया है कि हम देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी लें।

यूएनआरडब्ल्यूए बोला- फलस्तीनी बच्चों की पीढ़ी बर्बाद होने का खतरा

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के आयुक्त जनरल ने आगाह किया है कि फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए फंड में कटौती पर चिंता जाहिर की है। आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी ने चेतावनी दी है कि यूएन की इस एजेंसी के पतन से फलस्तीनी बच्चों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो जाएगी। लाजारिनी ने कहा कि अगर गंभीर वित्तीय संकट जारी रहता है तो एजेंसी के पतन का खतरा सचमुच वास्तविक है। उन्होंने आगाह किया कि बच्चों की एक पीढ़ी बलि चढ़ जाएगी, वे उचित शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा, यूएनआरडब्ल्यूए गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया में फैले लगभग छह मिलियन फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए जीवन रेखा है। अब तक लगभग 2.60 लाख बच्चे एजेंसी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं।

80 साल का इंतजार हुआ बेकार, पति से मिले बगैर विदा हुई 103 की हुझैन

बीजिंग, एजेंसी। 103 साल का जीवन जीने के बाद दुनिया से विदा हुई बुजुर्ग महिला की कहानी किसी को भी भावुक कर सकती है। उन्होंने 8 दशक से ज्यादा समय तक अपने बिछड़े पति का इंतजार किया, लेकिन सब बेकार रहा। आखिरी सांस लेते समय महिला ने यादगार के तौर पर तकिये का कवर अपने हाथों में रखा और दुनिया को अलविदा कह दिया। कहानी चीन की डू हुझैन की है। वह अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी सदियों तक लोगों को सुनाई जाएगी। उन्होंने दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझू प्रांत में 8 मार्च को अंतिम सांस ली। हालांकि, उनकी मौत की वजह परिवार की तरफ से सार्वजनिक नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके परिवार ने बताया है कि हुझैन की शादी 1940 में हुई थी।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, निधन से पहले हुझैन ने तकिये का कवर अपने हाथों में रखा था। खास बात है कि यह कवर उन्होंने अपनी शादी के समय इस्तेमाल किया था। वह पति हुआंग जुन्फू से तीन साल बड़ी थीं। खबर है कि शादी के तुरंत बाद ही हुआंग कुओमिंतांग सेना में शामिल हो गए थे और जंग के लिए निकल पड़े थे।

अब साल 1943 में यानी 3 साल के बाद हुझैन ने जुन्फू को खोज निकाला और उनके ही साथ रहीं, लेकिन गर्भवती होने के बाद वह घर लौट आईं। इसके बाद जनवरी 1944 में उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम हुआंग फचांग रखा

गया। हालांकि, जुन्फू इसके बाद भी घर लौटे थे, लेकिन कुछ ही समय में घर से दोबारा सेना के काम के लिए निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। वह खत भेजते रहे, लेकिन यह सिलसिला भी 15 जनवरी 1952 में खत्म हो गया।

कैसे काटे दिन : रिपोर्ट के अनुसार, जिस पेपर का जुन्फू ने इस्तेमाल किया था, उससे संकेत मिल रहे थे कि वह मलेशिया में चीनी निर्माण कंपनी में काम कर रहे थे। वहीं, उनका इंतजार कर रहीं हुझैन दिन में खेत पर काम करतीं और शाम को सैंडल और कपड़ों की बुनाई कर घर चलाती थीं। परिवार ने जुन्फू को खोजने की कई कोशिशें की, लेकिन सब बेकार रहीं। अगर वह लौट आए तो उनका परिवार बताता है कि उन्होंने शादी के लिए भी इनकार कर दिया था। वह कहती थीं, अगर वह एक दिन लौट आए तो? उनका बेटा फचांग 70 के दशक में स्कूल में शिक्षक बन गए थे और 2022 में उन्होंने भी अंतिम सांस ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जुन्यी काउंटी के सरकारी विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि जुन्फू 1950 में मलेशिया में रहने लगे थे।

जेलेंस्की ने सशस्त्र बलों के नए स्टाफ प्रमुख को किया नियुक्त

कीव, एजेंसी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लेफ्टिनेंट जनरल अनातोली बारहिलेविच की जगह मेजर जनरल एंड्री ह्नातोव को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति की वेबसाइट पर बारहिलेविच की बर्खास्तगी और ह्नातोव की नियुक्ति के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने फेसबुक पर लिखा कि सशस्त्र बलों में फेरबदल का उद्देश्य उनकी युद्ध कौशल को बढ़ाना है। उमेरोव ने एक फेसबुक पोस्ट में पदोन्नति की सराहना करते हुए कहा, हम यूक्रेन के सशस्त्र बलों को उनका युद्ध कौशल बढ़ाने के लिए व्यवस्थित रूप से बदल रहे हैं। उमेरोव ने उल्लेख किया कि ह्नातोव के पास 27 वर्षों से अधिक का सैन्य अनुभव है, उन्होंने पहले एक समुद्री ब्रिगेड, ऑपरेशनल कमांड ईस्ट के सैनिकों और यूक्रेनी सशस्त्र बलों के संयुक्त बलों की कमान संभाली है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, बारहिलेविच को सैन्य मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित

करने और सशस्त्र बलों के भीतर अनुशासन को मजबूत करने के मिशन के साथ मंत्रालय का मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है। बारहिलेविच ने फरवरी 2024 में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्य करना शुरू किया। रूस के साथ युद्ध के तीन साल से अधिक समय बाद, यूक्रेन धीरे-धीरे कई मोर्चों पर पीछे हट रहा है, क्योंकि वहां जनशक्ति की कमी है। कीव सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कमांड संस्कृति और संसाधन प्रबंधन जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल किया जा सके। नाटो भागीदारों के अनुभव का लाभ उठाते हुए, यूक्रेन वर्तमान में सामंजस्य में सुधार के प्रयास में ब्रिगेड के बजाय कोर सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहा है। उमरोव ने उसी फेसबुक पोस्ट में लिखा परिवर्तन जारी है। सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्तमान में लगभग 880,000 लोग यूक्रेनी सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युद्धकालीन चुनौतियों के बावजूद, देश ने सोवियत विरासत को त्यागने और अपनी सेना को अधिक कुशल बनाने के लिए परिवर्तन लागू किए हैं, युद्ध के अनुभव वाले युवा कमांडरों को नियुक्त किया है और नवाचारों का समर्थन किया है। पिछले साल यूक्रेन ने एक समर्पित मानव रहित प्रणाली बल की शुरुआत की थी। इस वर्ष की शुरुआत में, यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि देश अपनी ब्रिगेड आधारित प्रणाली से हटकर बड़ी इकाइयों की कोर प्रणाली की ओर बढ़ेगा, जिसका उद्देश्य 1,000 किलोमीटर से अधिक सीमावर्ती क्षेत्र में फैले अपने बलों के बीच समन्वय में सुधार करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

यूक्रेन में सीजफायर पर अब तक नहीं बनी बात, पुतिन को मनाने के लिए खुद फोन मिलाएंगे ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-जान लगाकर जुटे हुए हैं। इस सप्ताह इस दिशा में बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिला सकते हैं। वाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ भी लगातार संपर्क में है। इससे पहले अमेरिका ने पिछले सप्ताह दोनों देशों के सामने सीजफायर समझौते को लेकर 30 दिनों का एक प्रस्ताव रखा था। जहां यूक्रेन ने युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, वहीं पुतिन ने अभी इस पर सहमति नहीं जताई है।

विटकॉफ ने रविवार को सीएनएन के स्टेट ऑफ द यूनियन में इस मामले पर बातचीत करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह दोनों राष्ट्रपतियों की फोन कॉल पर बातचीत होगी। हम यूक्रेनियों के साथ भी बातचीत जारी रख रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा है कि पुतिन ने संभावित फोन कॉल से पहले विटकॉफ से ट्रंप को संदेश देने के लिए कहा था। पिछले सप्ताह विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात भी की थी।

पुतिन ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार : विटकॉफ ने पुतिन के साथ अपनी बातचीत को सकारात्मक बताया। विटकॉफ ने बताया, यह एक

समाधान-आधारित चर्चा थी। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उनका मानना ??है कि पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं और दोनों नेता जंग को खत्म करना चाहते हैं। विटकॉफ ने दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में किसी तरह का समझौता हो जाएगा।

क्या चाहता है रूस : बता दें कि सीजफायर डील के तहत यूक्रेन यह आश्वासन मांग रहा है कि भविष्य में रूसी हमले की स्थिति में अमेरिका और अन्य सहयोगी इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन वाइट हाउस इसके लिए प्रतिबद्धता जताने से हिचक रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि वह किसी भी स्थिति में अस्थायी युद्धविराम नहीं चाहता है।

नासा के ऑफिस में कॉक्रोचों का आतंक, टॉइलट पेपर भी नहीं; डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से परेशान कर्मचारी

वाशिंगटन, एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अगर सबसे ज्यादा परेशान हैं तो वे हैं सरकारी कर्मचारी। एक तरफ छंटनी दूसरी तरफ कटौती करने के लिए एक से एक तरीके अपनाने ने सरकारी और अनुबंधित कर्मचारियों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम संभालने के बाद तहलका ही मचा दिया है। अमेरिका की सरकार ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम छोड़कर ऑफिस आने का फरमान सुना दिया। 2020 में कोविड-19 के बाद से ही लाखों कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वहीं जब लोग ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि वहां टॉइलट पेपर तक नहीं है। ऑफिस में कॉक्रोचों ने कब्जा कर लिया है और बैठने के लिए डेस्क तक मौजूद नहीं है। यह हाल आम कार्यालयों का नहीं बल्कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी के ऑफिस का भी है। सरकारी कर्मचारियों को नए तरीके से काम में लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने कई बदलाव किए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कम से कम 1 लाख सरकारी कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से ही नौकरी छोड़ दी है। इसके बदल में उन्होंने मुआवजा ले लिया है। वहीं पड़े पैमाने पर छंटनी की तलवार अब भी लटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉइस ऑफ अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर दी है और कई चैनल बंद कर दिए हैं। एलन मस्क का कहना है कि विदेश में अमेरिका के खर्च पर प्रसारण करके केवल लोगों के टैक्स की बर्बादी की जा रही है। इसलिए एडिटर्स को भी छुट्टी पर भेज दिया गया और कई चैनलों पर समाचारी की जगह सिर्फ संगीत ने ले ली है।

नासा के ऑफिस में बुरा हाल : पिछले साल अगस्त में बजट के मुताबिक लगभग 2

लाख से ज्यादा कर्मचारी घर से काम कर रहे थे। वहीं यह काम 11 लाख लोगों से लिया जा सकता है। पिछले महीने वॉशिंगटन स्थित नासा के हेडक्वार्टर में भी कर्मचारी अपने काम पर लौटे तो उनका सामना कॉक्रोच से हुआ। खटमल, कॉक्रोच और अन्य कीड़े ऑफिस पर कब्जा कर चुके थे। वहीं कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कुर्सियां और डेस्क तक मौजूद नहीं थीं। टॉइलेट पेपर खत्म हो गए थे।

नासा के करीब 8 हजार कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया गया है। उनका कहना है कि बिना कंप्यूटर और डेस्क के काम करना संभव ही नहीं है। मैरीलैंड के नासा ऑफिस के कर्मचारी भी ट्रैफिक से परेशान हो गए। वहीं यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विस के ऑफिस के कर्मचारी भी अपनी डेस्क ही ढूंढते रह गए। कई कर्मचारियों को संदूकों पर बैठकर काम करना पड़ा। कई कर्मचारियों का कहना है कि ऑफिस लौटना चिड़ियाघर जाने जैसा हो गया है जहां टॉइलेट में टिशू तक मौजूद नहीं है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत के उधना इलाके में 'राहुल अपार्टमेंट' गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

गैंग लीडर राहुल पिंपड़े के तीन अवैध मकानों पर चला बुलडोजर

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के उधना इलाके में 'राहुल अपार्टमेंट' गैंग चलाने वाले राहुल पिंपड़े पर अब कानून का शिकंजा और कड़ा हो गया है। उधना पुलिस ने सख्त बंदोबस्त के साथ 18 मार्च 2025 आरोपी राहुल के तीन अवैध मकानों को तोड़ दिया।

प्रशासन के मुताबिक, राहुल ने सरकारी आवास के पास अवैध निर्माण किया था, जिसे नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने आवास के अंदर भी गैरकानूनी निर्माण किया था, जिसे तोड़ दिया गया।

अवैध गतिविधियों का हेडक्वार्टर था मकान जांच में सामने आया कि राहुल पिंपड़े ने ये तीन मकान गैरकानूनी तरीके से बनाए थे और इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए करता था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये तीनों मकान 'राहुल अपार्टमेंट' गैंग का मुख्य अड्डा थे, जहां से वह आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता था।

22 संगीन अपराधों में आरोपी है राहुल राहुल पिंपड़े 'सूर्या मराठी' मर्डर केस का आरोपी है और उसके खिलाफ गुजसीटोक, मारपीट, हत्या सहित 22 मामले दर्ज हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद उसके गैंग की कमर टूट गई है। राहुल अपार्टमेंट गैंग के लीडर के मकान पर चला बुलडोजर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 मकान ढहाए गए अवास के मकान के अंदर भी आरोपी का अवैध निर्माण तोड़ा गया सूरत पुलिस ने राहुल अपार्टमेंट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उधना इलाके में गैंग लीडर राहुल के तीन अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल इन मकानों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए करता था। इतना ही नहीं, उसने सरकारी आवास के अंदर भी गैरकानूनी निर्माण कर रखा था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया।

इस दौरान पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त रखा और किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई।

इस्तीफे की मांग करते हुए सड़क पर NSUI चक्का जाम कर दिया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत में ड्रग्स और शराब जैसी नशीली चीजों की खुलेआम बिक्री को लेकर NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़क पर चक्का जाम कर दिया।

पुलिस ने किया लाठीचार्ज,10 कार्यकर्ता हिरासत में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और 10 लोगों को हिरासत में लिया। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुजरात में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है।

क्या है मामला?

- ड्रग्स और अवैध शराब की बिक्री को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं।
- NSUI ने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार की मिलीभगत से यह कारोबार फल-फूल रहा है।
- गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया।
-पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया और 10 को हिरासत में लिया।

NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन और तेज करेंगे।

गुजरात में ड्रग्स एक्ट और शराबबंदी के बावजूद जारी है अवैध कारोबार: NSUI

NSUI कार्यकर्ता दुष्यंत राजपुरोहित ने कहा कि वडोदरा में हाल ही में हुए "हिट एंड रन" मामले में एक महिला की मौत हो गई थी और सात लोग घायल हुए थे।

- इस हादसे में शामिल ड्राइवर नशे की हालत में था और उसने ड्रग्स का सेवन किया था।
- गुजरात में ड्रग्स एक्ट और शराबबंदी लागू होने के बावजूद ड्रग्स और शराब का अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा है।

गुजरात में ड्रग्स का खतरा बढ़ा: NSUI

-NSUI ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है।

लफंगे तत्वों के आतंक के चलते प्रशासन एक्शन मोड में, सूरत में 500 अपराधियों की बनाई सूची

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत सामाजिक तत्वों और अपराधियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरत पुलिस ने 500 अपराधियों की सूची तैयार की है, जबकि कच्छ पुलिस ने 1900 अपराधियों को चिन्हित किया है।

पुलिस प्रशासन अब इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूरत और कच्छ में हाल ही में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है।

गुजरातभर में असामाजिक तत्वों का आतंक पिछले काफी समय से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय डीजीपी विकास सहाय ने इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं होगी।

इसी उद्देश्य से सूरत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सूरत पुलिस ने अब तक 500 से अधिक अपराधियों की सूची तैयार की है और चेतावनी दी है कि यदि वे अपराध गतिविधियां नहीं छोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ गुजसीटोक (GU-JCTOC) के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मिल रही जानकारी के अनुसार, सूरत शहर में ये 9 गैंग सक्रिय हैं:

1. **आसिफ टमेटा गैंग**
2. **सज्जु कोठारी गैंग**
3. **सूरज कालिया गैंग**
4. **विपुल गाजीपारा गैंग**
5. **राहुल अपार्टमेंट गैंग**
6. **लालू जालीम गैंग**
7. **बेंटी गैंग**
8. **असरफ नागौरी गैंग**
9. **मींडी गैंग**

असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अब पुलिस टपोरी, हिस्ट्रीशीटर, एनसीआर रिकॉर्ड वाले अपराधियों और अन्य असामाजिक तत्वों की भी सूची बना रही है। इन लोगों को चेतावनी दी जाएगी कि अगर वे नहीं सुधरते हैं, तो उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

पूर्व कच्छ पुलिस ने 1900 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की

डीजी के आदेश के बाद पूर्व कच्छ पुलिस ने यह सूची तैयार की है। अब पूर्व कच्छ में आतंक मचाने वाले असामाजिक तत्वों की खैर नहीं। पूर्व कच्छ पुलिस ने नामांकित गुंडों और अपराधी तत्वों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया है। इस सूची में बलात्कार, हत्या, खनिज चोरी, लिस्टेड बूटलेगर, कुख्यात तेल चोर और अन्य अपराधियों को शामिल किया गया है।

पुलिस अब इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

1300 अपराधियों की सूची तैयार की गई

राज्य पुलिस प्रमुख विकास सहाय ने 100 घंटे के भीतर पूरे गुजरात में असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के मिलते ही डीसीपी भावेश रोजिया ने कहा कि असामाजिक तत्वों, बॉडी ऑफेंस, संगठित अपराध और प्रॉपर्टी ऑफेंस में शामिल अपराधियों की सूची तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सूरत क्राइम ब्रांच ने इस लक्ष्य के तहत विशेष जांच शुरू की है, जिसमें 1300 अपराधियों की पहचान की गई है। आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'मम्मी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती से मोबाइल गिर गया'

लिखकर सूरत में 12 साल की बच्ची ने की आत्महत्या।

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कतारगाम में रहने वाले दंपती की 12 साल की बेटी से गलती से मोबाइल पानी से भरी बाल्टी में गिर गया, जिससे डरकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची ने सुसाइड नोट में लिखा था,

कतारगाम रोड पर जय रणछोड़ अपार्टमेंट में रहने वाली 12 वर्षीय जैनिसा कपिल धुधल ने रविवार शाम आत्महत्या कर ली। जब उसकी मां किसी काम से बाहर गई हुई थी और उसके पिता भी घर पर नहीं थे। इस दौरान उसने एक कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली।

जब उसकी छोटी बहन ने यह देखा तो घबराकर चिल्लाने लगी, जिससे पड़ोसी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उसका शव स्मीमेर अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने बताया कि जैनिसा ने सुसाइड नोट में लिखा था, "मम्मी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती से मोबाइल फोन गिर गया। तू मुझे माफ कर देना, मैं फांसी लगा रही हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत। मेरे भाई कन्नू और छोटी बहन का ख्याल रखना।"

पुलिस के अनुसार, पानी से भरी बाल्टी में मोबाइल गिर जाने से वह घबरा गई थी और तनाव में आकर उसने यह कदम उठा लिया। परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। जैनिसा के पिता कपिलभाई मुंबई महानगर पालिका में नौकरी करते हैं, जबकि उसकी माँ सूरत महानगर पालिका में कार्यरत हैं। बच्ची की मौत से परिवार में शोक छा गया है।

गृह मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ही क्षेत्र में अपराधी बेखौफ,अपराध बेलगाम।

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर में दिनदहाड़े अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 वर्षों में सूरत शहर और जिले में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, दुष्कर्म, रंगदारी, वसूली, धोखाधड़ी और महिला अत्याचार के कुल 9031 मामले दर्ज हुए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सूरत में हर दिन 17 अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। प्रतिदिन 7 चोरी, 2 धोखाधड़ी और दुष्कर्म व महिला अत्याचार के 1-1 मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

सूरत शहर और जिले में अपराध के आंकड़ों की बात करें तो -

- चोरी के 4889 मामले
- लूट के 108 मामले
-डकैती के 28 मामले
-अपहरण के 602 मामले
-हत्या के 266 मामले
-दुष्कर्म के 647 मामले
-रंगदारी के 47 मामले
-वसूली के 79 मामले
-धोखाधड़ी के 1595 मामले
-महिला अत्याचार के 767 मामले दर्ज किए गए हैं।

खुद गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि अभी भी 1795 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

'भाजपा का खेस पहने हुए बूटलेगर्स कितने हैं, इसकी भी सूची जारी करनी चाहिए'

विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि राज्य में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। भू-माफिया और खनन माफिया बेखौफ होकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। असामाजिक तत्व और बूटलेगर्स खुलेआम सड़कों पर दबंगई कर रहे हैं। आम नागरिकों और उनकी जान-माल पर हमले हो रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि गुंडा तत्वों को न तो सरकार का डर है और न ही पुलिस का।

अमित चावड़ा ने आगे कहा, "जब पुलिस की पोल खुली, तब सफाई में जागी सरकार अब बूटलेगर्स और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है।

लेकिन इसमें भाजपा से जुड़े बूटलेगर्स कितने हैं?

भाजपा नेताओं से सांठगांठ रखने वाले कितने बूटलेगर्स हैं? भाजपा का खेस पहने हुए बूटलेगर्स कितने हैं?

इसकी भी सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। ताकि यह साफ हो सके कि असामाजिक तत्वों और बूटलेगर्स की संख्या से ज्यादा भाजपा का संरक्षण पाने वाले असामाजिक तत्व हैं।"

"प्रोत्साहन-2025" इंटर कॉलेज इवेंट का हुआ आयोजन

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,भगवान महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज (BMCCMS), सूरत द्वारा "प्रोत्साहन 2025" इंटर कॉलेज ईवेंट का आयोजन मंगलवार को किया गया।

कॉमिकॉन थीम पर आधारित आयोजन में छात्र स्पाइडर-मैन, बैटमैन, डेडपूल, हल्क आदि पात्रों की वेशभूषा में शामिल हुए।

कार्यक्रम का उद्घाटन सूरत के कलेक्टर आईएएस डॉ. सौरभ पारधी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया।

भगवान महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉ. चेता देसाई ने बताया की कार्यक्रम में क्विज़, डिबेट, आईपीएल ऑक्शन, युवा संसद, नृत्य, गायन, फैशन शो आदि जैसी प्रतियोगिताएँ हुईं।

खेलकूद में बॉक्स क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कराटे, ई-स्पोर्ट्स जैसे खेल आयोजित किए गए।

कलात्मक इवेंट्स में फायरलेस कुकिंग, फेस पेंटिंग, मेहंदी, टैटू और पोस्टर मेकिंग आदि के अलावा स्क्विड गेम, गरबा, ट्रेजर हंट और खतरों के खिलाड़ी जैसे मनोरंजक खेल भी हुए। आयोजन का समापन रविवार को होगा।